● वर्ष-3
● अंक-301
रायपुर, मंगलवार
30 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› सावन की पहली एकादशी कामिका...

15 लाख पात्र परिवारों को जल्द मिलेगा पीएम आवास

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री चौहान से की मुलाकात

रायपुर/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ थे। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होने कहा दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधार आधारित भुगतान में कठिनाई आ रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की। साथ ही, मुख्यमंत्री साय ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 वृहद पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी।

सुप्रीम कोर्ट के मामले निपटाने विशेष लोक अदालत

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कम करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली विशेष लोक अदालत शुरू की है। लोक अदालत 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लगेगी। लोक अदालत हर दिन दोपहर 2 बजे के बाद आयोजित की जाएगी और मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, एक वरिष्ठ वकील और एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड होंगे। इस मौके पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पूरे हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचों द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारा अनुभव यह था कि यह एक ज़बरदस्त सफलता थी। लोक अदालत जिसमें बार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का सहयोग है और उच्च न्यायालयों, राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों द्वारा व्यापक जमीनी काम किया गया है। सीजेआई ने आगे कहा कि विचार यह है कि छोटे-छोटे मामले निपटाए जाएं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि सुप्रीम कोर्ट में छोटे-छोटे

मामले कैसे आते हैं। इसलिए हमने सेवा विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, चेक अनादरण मामले से जुड़े मामलों को चुना। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीशों के साथ लोक अदालत पैनल के हिस्से के रूप में बार सदस्यों की उपस्थिति ने पूरे समाज में सही संदेश भेजा है कि हम न्याय करने के अपने प्रयासों में एकजुट हैं, खासकर इन छोटे मामलों में शामिल नागरिकों को। मुझे उम्मीद है कि यह लोक अदालत अब भविष्य में उच्चतम न्यायालय में संस्थागत हो जायेगी। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे एक मामला याद है जिसमें पति ने तलाक की कार्यवाही पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की थी और उसकी पत्नी ने भरण-पोषण की कार्यवाही दायर की थी और बच्चों की कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी। प्री-लोक अदालत की बैठक में दोनों एक साथ आए और दोनों ने फैसला किया कि वे साथ रहेंगे। इसलिए जब वे दोनों लोक अदालत के सामने आए, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुशी-खुशी साथ रहने का फैसला किया है। पत्नी ने कहा कि मुझे भरण-पोषण नहीं चाहिए क्योंकि हम बहुत खुशी से साथ रह रहे हैं। सीजेआई ने कहा, ''अपने सभी सहयोगियों और उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की ओर से, मैं उन सभी नागरिकों या वकीलों से अपील करूंगा, जिनके मुकदमे उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं कि वे अपने मुकदमों का तेजी से निपटारा करने की कवायद के तहत इस अवसर का फायदा उठाएं।

शहीद अग्निवीरों पर राहुल के दावे को रक्षा मंत्रालय ने बताया गलत

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अग्निवीर वाले दावे को रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने खारिज किया है। यह कहा गया कि मिलिट्री सर्विस के दौरान जान गंवाने वाले किसी भी अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जाती है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि इसमें बीमा और दूसरी मदें भी शामिल हैं। दरअसल, राहुल गांधी ने आज लोकसभा में कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि शहीद अग्निवीर के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। मगर, उनकी बात गलत थी। उन्होंने कहा, उस परिवार को बीमा दिया गया था, मुआवजा नहीं। यह सच है।

इसे कोई नकार नहीं सकता। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, अगर मिलिट्री सर्विस के दौरान किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलती है। इसमें 48 लाख रुपये का बीमा है, जिस पर अग्निवीर से कोई भुगतान नहीं लिया जाता है। 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, सेवा निधि पैकेज लगभग 11.70 लाख रुपये और सर्विस की शेष अवधि के लिए वेतन भी शामिल है। इसके अलावा, अग्निवीरों को 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर भी मिलता है, जिसे लेकर सरकार ने कई बैंकों के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है।

राहुल गांधी के बयान पर क्या बोले राजनाथ सिंह - वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने अग्निवीरों पर देश को गुमराह करने का प्रयास किया। साथ ही, उन्होंने बजट पर भ्रांति पैदा की है। राहुल ने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया। बजट में अग्निवीरों को पेंशन के लिए रुपया नहीं दिया गया। उनका भाषण संपन्न होने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, 'नेता प्रतिपक्ष ने बजट से संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, उस पर वित्त मंत्री जवाब देते समय बात करेंगी। मेरा मानना है कि बजट को लेकर कई भ्रांतियां पैदा की गई हैं।' उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है। सेना से जुड़े अग्निवीरों को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जब भी आपका (लोकसभा अध्यक्ष) आदेश होगा मैं अग्निवीरों को लेकर अपना बयान देने के लिए तैयार हूं।

क्या फिर से कारगिल जैसा युद्ध होने वाला है?

जम्मू। जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तानी सेना के विशेष सेवा समूह (एसएसजी) का हाथ है। इन सब के बीत सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। बताया जा रहा है कि भारत में हुए इन हमलों की पूरी रणनीति पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो के जीओसी

आदिल रहमानी बना रहा था। इतना ही नहीं, आदिल रहमानी जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी दोनों में हमले की सोची-समझी रणनीति पर काम कर रहा है। 27 जुलाई को कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम (बीएटी) की संलिप्तता जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानी सेना की सीधी भागीदारी की पुष्टि करती है। पूर्व डीजीपी डॉ. एसपी वैद का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में हो रहे हमलों के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना का हाथ है। डॉ. वैद के मुताबिक ये एक गुप्त युद्ध है और भारत को इसका जवाब इसी तरह देना होगा। डॉ. एसपी वैद ने बताया कि आदिल रहमानी की निगरानी में इस ऑपरेशन के लिए करीब 600 एसएसजी कमांडो को लगाया गया है। इन उच्च प्रशिक्षित कमांडो को क्षेत्र में हवाई मार्ग से उतारा गया है, जिनमें से कई पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि कमांडो का नेतृत्व पाकिस्तानी सेना के विशिष्ट एसएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम कर रहे हैं, जो जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और इन कमांडो और आतंकवादियों को हमले करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ पूर्व डीजीपी एसपी वैद बल्कि एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने भी सोशल मीडिया पर यही दावा किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कथित तौर पर एसएसजी जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) मेजर जनरल आदिल रहमानी जम्मू क्षेत्र में हमले करा रहे हैं। 2. कहा जाता है कि एसएसजी की एक पूरी बटालियन घुसपैठ कर चुकी है यानी कम से कम 600 कमांडो कुपवाड़ा क्षेत्र और अन्य जगहों पर हैं। 3. स्थानीय जिहादी स्लीपर सेल सक्रिय हैं और भारतीय क्षेत्र के अंदर एसएसजी आंदोलन में सहायता कर रहे हैं।

प्रमुख समाचार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अफजाल की सजा को रद्द किया

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में सांसद अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि और उन्हें सुनाई गई चार साल की सजा को सोमवार को रद्द कर दिया। इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी पर खतरा समाप्त हो गया और वह सांसद बने रहेंगे। न्यायमूर्ति एसके सिंह ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गाजीपुर की अदालत के निर्णय को रद्द करने का आदेश पारित किया। इसके साथ ही, अदालत ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है। वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था। गाजीपुर की सांसद-विधायक विशेष अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।

इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा पर रोक

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी, जिसमें शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी पूर्व मीडिया अधिकारी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति एस सी चांडक की एकल पीठ ने सोमवार को याचिका को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और तब तक के लिए अंतरिम रोक बढ़ा दी। सीबीआई की विशेष अदालत ने 19 जुलाई को जमानत पर रिहा मुखर्जी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में दस दिनों के लिए यूरोप (स्पेन और ब्रिटेन) की यात्रा करने की अनुमति दी थी। सीबीआई के अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट ने तर्क दिया था कि मुखर्जी को देश से बाहर (यात्रा के लिए) जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह विचाराधीन मुख्य आरोपी हैं। विशेष अदालत ने मुखर्जी को यात्रा के दौरान (स्पेन और ब्रिटेन में) भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन कार्यालयों में उपस्थित होने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा दो लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करने का निर्देश दिया था।

भारत-बांग्लादेश समझौते पर भड़की ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि वे बांग्लादेशियों से प्यार करती हैं लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सरकार तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच किसी भी समझौते को मान जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य को बांटने की कोशिश कर रही है। ममता का कहना था कि तीस्ता नदी के जल के बंटवारे का सीधा मतलब उत्तरी बंगाल के लोगों को पानी से वंचित करना होगा, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच किसी भी समझौते का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश की जनता से प्रेम करती है, लेकिन तीस्ता नदी के जल के बंटवारे का मतलब उत्तरी बंगाल के लोगों को पेयजल तक से वंचित करना होगा। पश्चिम बंगाल में भूमि कटाव नियंत्रण और बाढ़ की रोकथाम से संबंधित प्रस्ताव पर विधानसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि तीस्ता नदी में सर्दी और गर्मी के मौसम में बहुत कम पानी होता है।

शरद ने महाराष्ट्र में मणिपुर जैसी अशांति की आशंका पर चिंता जताई

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मणिपुर जैसी अशांति की आशंका पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि देश के विकास के लिए सामाजिक एकता जरूरी है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह ऐसा क्यों सोचते हैं। रविवार शाम को सामाजिक एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने मणिपुर में जातीय संघर्ष से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की भी आलोचना की। मणिपुर में पिछले साल मई में शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। पवार ने कहा, ''हमारे देश के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामाजिक एकता आवश्यक है। तनाव और विभाजन की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। देश में बढ़ते मतभेद के लिए जाति, धर्म और से परे एकता की आवश्यकता है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सरकार की है।'' उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। मणिपुर में पिछले साल मई से ही बहुसंख्यक मेइती समुदाय और कुकी आदिवासियों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हुई।

भाजपा में बृजभूषण शरण सिंह का चैप्टर खत्म

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और छह बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के चर्चित नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अब भाजपा उनको मौका नहीं देगी। बृजभूषण शरण सिंह ने भाजपा के फिर मौका देने के सवाल पर कहा कि भाजपा अब उन्हें कभी मौका नहीं देगी। पूर्व सांसद ने कहा कि वो जानते हैं कि पार्टी उन्हें अब मौका नहीं देगी। सिंह ने कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते, जिनको देखना है, उनको देखने दीजिए। बताते चलें कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगने के बाद कुश्ती संघ में कुर्सी गंवा चुके कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुकदमे का सामना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को लड़ा दिया था। करण भूषण सिंह ने सपा के राम भगत मिश्रा को लगभग डेढ़ लाख वोट के अंतर से हराकर अपने पिता की सीट पर भाजपा का कब्जा कायम रखा। बृजभूषण शरण सिंह के एक और बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोण्डा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। सोमवार को परसपुर में समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश सिंह के परिजनों से मिलने के बाद पूर्व सांसद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

2024 बजट निर्धारित करता है देश की वित्तीय दिशा और मोदी सरकार की राजनीतिक स्थिरता

कल्याणी शंकर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह 2024-25 का बजट पेश किया, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया। 2024 के आम चुनावों के बाद पहला बजट, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अगले 5 वर्षों के लिए वित्तीय दिशा निर्धारित करता है और मोदी सरकार की राजनीतिक स्थिरता को दर्शाता है। तीसरी बार शपथ लेने के एक महीने बाद मोदी 3.0 के पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए उदार समर्थन दिखाया गया।

इस कदम की विपक्ष ने आलोचना की, जिन्होंने कहा कि यह राजनीतिक जरूरतों से प्रेरित बजट है और भाजपा के सहयोगियों को खुश करने के लिए विपक्ष द्वारा शासित राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। एन.डी.ए. सरकार की स्थिरता तेलुगु देशम पार्टी और जद (यू) पर निर्भर करती है, जिनके लोकसभा में क्रमशः 16 और 12 सदस्य हैं। दोनों ही दल अपने राज्यों के विकास के लिए विशेष दर्जे या वित्तीय मदद की मांग कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण समर्थन दिखाया गया, जो गठबंधन की राजनीति को दर्शाता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने दोनों राज्यों के लिए वित्तीय सहायता और विकास परियोजनाओं की एक शृंखला की रूपरेखा तैयार की। कांग्रेस ने बजट को रणनीतिक कदम के रूप में देखा, जिसने सहयोगियों को पर्याप्त धन मुहैया कराया। उन्होंने इसे इन 2 सहयोगियों को पुरस्कृत करके मोदी सरकार की स्थिरता को सुरक्षित करने के प्रयास के रूप में देखा, जिससे राजनीतिक खेल में चल रही चालों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। तेलुगु देशम पार्टी और जद (यू) भाजपा सरकार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

एन.डी.ए. सरकार की मजबूत पकड़ काफी हद तक तेलुगु देशम पार्टी और जद (यू) पर निर्भर करती है। उनके नेता मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठकों में अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय मदद की पैरवी कर रहे हैं। यह 'विशेष मदद' अक्सर केंद्रीय निधियों या अनूठी विकास परियोजनाओं के उच्च हिस्से को संदर्भित करती है। दोनों दल अपने राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए जोरदार वकालत करते हैं। दोनों राज्यों को मिलने वाले भारी लाभ संभवतः सरकार के समर्थन के लिए भाजपा के बीच हुए समझौते का हिस्सा थे। इसलिए, मोदी ने उनके निरंतर समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए समझौते के पहले भाग को पूरा किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में बिहार को बदलने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। नए हवाई अड्डों, मैडीकल कॉलेजों, खेल के बुनियादी ढांचे और 2,400 मैगावाट वाले बिजली संयंत्र की स्थापना सहित इन योजनाओं से राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडऩे और राज्य के भाजपा-जद(यू) गठबंधन के लिए जनता का समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे लोगों को राजनीतिक गतिशीलता में दिलचस्पी होगी।

आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार की सौगात में इसकी नई राजधानी अमरावती का निर्माण शामिल है। 10 साल पहले, तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने की पहल की थी। हालांकि, वे सत्ता से बाहर हो गए और उनके उत्तराधिकारी जगन मोहन रैड्डी ने इस विचार का समर्थन नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने आंध्र प्रदेश के 3 क्षेत्रों में 3 राजधानी शहरों का प्रस्ताव रखा। हाल ही में, अदालत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे नायडू को अपने सपनों की परियोजना पर आगे बढऩे की अनुमति मिल गई। 15,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता बहुपक्षीय विकास एजैंसियों के माध्यम से दी जाएगी, जिसके बाद में और अधिक धन जुटाया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के दायित्वों को पूरा करने का स्पष्ट वचन दिया है, जिसमें पोलावरम सिंचाई परियोजना को वित्तपोषित करना और पूरा करना शामिल है, जो राज्य के विकास को आश्वस्त करता है।

मोदी के आलोचकों को लगा कि गठबंधन धर्म निभाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे सहजता से किया है। हालांकि मोदी ने दोनों सहयोगियों के साथ अपने समझौते के वित्तीय सहायता वाले हिस्से को पूरा कर लिया है, लेकिन भविष्य में और भी मांगें उठ सकती हैं। इसमें मोदी द्वारा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। उन्हें अपने बहुमत प्राप्त करने तक इन दोनों सहयोगियों को खुश रखना चाहिए। मोदी भाजपा के मुख्य मुद्दों को लागू कर सकते हैं, जैसे समान नागरिक संहिता लागू करना, जनसंख्या नियंत्रण करना और 2 सहयोगियों की मदद से अन्य आर्थिक सुधार करना। भाजपा के पर्यवेक्षकों का कहना है कि धीरे-धीरे पार्टी अलग-अलग दलों के सदस्यों को आकर्षित करेगी और कुछ सांसदों को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए राजी करेगी। फिलहाल, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को अपनी भूमिका मिल गई है, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें अपनी अहमियत खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुल मिलाकर, 2024 का बजट बिहार-आंध्र वाला था, जो गठबंधन की मजबूरियों से प्रेरित था। विशेष दर्जे की जगह विशेष पैकेज की उनकी मांग है।

जिला न्याय पालिका भारतीय न्याय प्रणाली की नींव : बीआर गवई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पहली बार भारत में जिला न्याय पालिका की वर्तमान चुनौतियों व भूमिका पर राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस का आयोजन रविवार को किया गया। इस कांफ्रेंस के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई थे और विशिष्ट अतिथि के रुप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा उपस्थित थे। इस कांफ्रेंस की विशेषता यह थी कि पहली बार न्यायिक इतिहास के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायमूर्तियों ने एक साथ शिरकत की और अपना विचार रखें।

इस राज्य स्तरीय कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने जिला न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी न्यायाधीशगण एक न्यायिक परिवार है और इसमें कोई अधीनस्थ नहीं है। न्यायमूर्ति ने जिला न्यायपालिका की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली की रीढ़ और आधार है और बिना मजबूत जिला न्यायपालिका के मजबूत न्यायिक प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती। जिला न्यायपालिका के लिए आधारभूत संरचना, आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी ज्ञान पर बल देते हुए किया कि आधुनिक तकनीकी जिला न्यायपालिका के लिए आवश्यक है और धीरे-धीरे न्यायपालिका को वर्चुअल कोर्ट की तरफ जाना है, जिसके लिए आधुनिक तकनीकी ज्ञान व संसाधनों से सुसज्जित होना आवश्यक है।

माननीय न्यायमूर्ति ने एक आदर्श न्यायाधीश द्वारा धारित किए वाले गुणों के बारे में बताया कि न्यायाधीश को शिष्टता के साथ सुनवाई करनी चाहिए, बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर देना चाहिए, सौम्यता के साथ विचार करना चाहिए और निष्पक्षता के साथ निर्णय करना चाहिए। न्यायमूर्ति द्वारा बताया गया कि न्यायाधीशगणों को सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल देना चाहिए और जेल में निरूद्ध बंदियों की संख्या और माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित जमानत आवेदनों के संदर्भ में विशेष रूप से व्यक्त किया गया कि बंदियों को जमानत देना एक नियम है जबकि जमानत निरस्त करना एक अपवाद है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में व्यक्त किया कि एक न्यायाधीश का आचरण कोर्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक न्यायाधीश को न्यायालय में बोलते हुए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति ने जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान में कुशल होने पर बल दिया और बताया कि न्यायाधीशगण का कार्य दैवीय कृत्य है और इसका बहुत सतर्कता और सावधानी से न्यायसंगत तरीके से निर्वहन किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि जिला न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक सशक्त व निडर जिला न्यायपालिका ही जमीनी स्तर पर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में और न्याय प्रदान करने में सक्षम होगी। माननीय न्यायमूर्ति ने इस बात पर बल दिया कि न्यायिक प्रणाली में लोगों के विश्वास को संरक्षित व सवंर्धित करने में व लोगों को समय पर न्याय प्रदान करने में जिला न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अपने स्वागत भाषण में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिगण का छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में आयोजित राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया। माननीय न्यायमूर्ति ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि सभी के सामूहिक प्रयासों से हम एक सशक्त व प्रभावी जिला न्यायपालिका को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। माननीय न्यायमूर्ति द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि आज की यह कान्फ्रेंस अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा और हम लोग जिला न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों को और बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होंगे तथा और अधिक सशक्त व प्रभावी जिला न्यायपालिका बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। इस राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र के समापन पर न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।

सावन के दूसरे सोमवार पर गूंजा हर-हर, बम-बम

कबीरधाम। 29 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले व ऐतिहासिक भोरमदेव के शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। भोरमदेव मंदिर में सुबह से हजारों की संख्या में कांवड़िये पहुंचे हैं। मंदिर हर-हर महादेव गूंज रहा है।

एमपी के अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर कांवडिये पूरे उत्साह, जोश और श्रद्धा के साथ आज सुबह यहां पहुंचे हैं। इनका क्रम पूरे दिनभर चलेगा। बोल बम, बोल बम के जयकारे लगाते हुए कांवडिये धर्मनगरी कवर्धा के बाबा भोरमदेव, बूढ़ा महादेव और जलेश्वर दादा डोंगरिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमरकंटक से कांवड़ उठाकर पैदल चल रहे कांवड़ियों के पैरों में छाले भी उनके कदमों को रोक नहीं पा रहे हैं। कांवड़ियों की तपस्या और श्रद्धा को देखते हुए कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निर्देश पर अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक कांवड़ियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन सहित ठहरने की उचित इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही अमरकंटक से लेकर भोरमदेव मंदिर लगभग 150 किलोमीटर के सफर में कांवड़ियों के लिए 20 से अधिक स्थानों पर ठहरने की विशेष व्यवस्था, अमरकंटक में निशुल्क भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। जिला बोल बम समन्वय समिति के निशांत झा, सुधीर केशवानी, दौवा गुप्ता ने बताया कि मृत्युंजय आश्रम में कांवड़ियों के लिए भोजन, प्रसादी और उनके ठहरने की निशुल्क व्यवस्था की है। इसके अलावा भोरमदेव मंदिर में भी कांवड़ियों के लिए भी यही व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था पूरे सावन माह तक रहेगी।

शहीदी सप्ताह में कांकेर शहर के पास पहुंचे नक्सली, सड़क किनारे बांधे नक्सली बैनर

भारी मात्रा में पर्चे भी फेंके

कांकेर। बस्तर में शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली शहर के पास पहुंच रहे हैं। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर मलांजकुड़म रोड पर नक्सलियों ने सड़क किनारे बैनर बांधे हैं। नक्सली बैनर के पास बड़ी संख्या में नक्सली पर्चे भी फेंके गए। हालांकि पर्चे लगातार हो रही बारिश में भीग चुके हैं।

मलांजकुड़म रोड पर बांधे गए बैनर में नक्सलियों ने लिखा है 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है। शहीद सप्ताह गांव, पंचायत, कस्बों, गलियों, शहर में क्रांतिकारी संकल्प के साथ मनाएंगे। लगातार मुठभेड़ में नक्सलियों को हो रहे नुकसान को लेकर नक्सलियों ने लिखा है नक्सली छापामार युद्ध नियमों का सृजनात्मक रूप से पालन करेंगे, ताकि अनावश्यक नुकसान को कम किया जा सके। गुरिल्ला युद्ध में विजय का अनुपात बढ़ाने का भी उल्लेख बैनर में है।

कांकेर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिसके कारण इस रोड पर लोगों की आवाजाही कम है लेकिन बड़ी संख्या में लोग मलांजकुडुम का प्राकृतिक सौंदर्य देखने पहुंच रहे हैं। पुलिस को भी नक्सली बैनर की जानकारी मिली। कांकेर टीआई मनीष नागर ने बताया की बैनर की सूचना मिली थी जिसे सड़क से हटवा दिया गया है।

नक्सली हर साल अपने मारे गए नक्सलियों की याद में शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। इस दौरान अपने मारे गए नक्सल साथियों की गाथाओं को आम जनता को सुनाते हैं। उनकी याद में स्मारक बनाते हैं। इसके अलावा नक्सल संगठन का संदेश बैनर और पर्चों के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सल हिंसक गतिविधियां कम होती हैं। इस दौरान नक्सली अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं।

नक्सल जानकारों के मुताबिक साल 1990 से 2000 के दशक में नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी के 3 सदस्य श्याम, मुरली और महेश पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए थे। तब से नक्सली नियमित रूप से 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाते आ रहे हैं। माओवादियों के शहीदी सप्ताह को देखते हुए पूरे बस्तर संभाग में पुलिस अलर्ट पर है। अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग तेज कर दी गई है।

स्कूल से रहते हैं गुल, फिर भी वेतन लेते हैं फुल

बीजापुर। शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी उसूर के अभयदान की वजह से पुसबाका प्रधान पाठक की खूब मौज है।नक्सल आतंक को ढाल बनाकर शिक्षक अपने मूल स्कूलों में सेवाएं नहीं दे रहे हैं।आरोप ये हैं कि प्रधानपाठक पिछले छह महीने से बिना स्कूल गए वेतन उठा रहे हैं।इस मामले में एक बात तो साफ कर दी है कि शिक्षकों ना तो नियमों की कद्र है और ना ही एक्शन का डर।तभी तो बिना बच्चों को पढ़ाए हर महीने सरकारी पैसा उड़ाना उनकी आदत बन गई है। आईए आपको बताते हैं आखिर वो महान शिक्षक कौन हैं।

बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में एक मामला प्रकाश में आया है।प्राथमिक शाला पुसबाका के प्रधान पाठक रामकृष्ण पेदमपल्ली ने 6 माह से स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दिया है।इसके बाद भी वो वेतन लेकर मौज कर रहे हैं।वेतन के पैसों से बिरयानी खाई जा रही है,खूब पार्टी की जा रही है।लेकिन जिस काम के लिए पैसा लिया जा रहा है वो काम नहीं हो रहा है।पूरा स्कूल बिना प्रधानपाठक के ही संचालित हो रहा है। कांग्रेस सरकार में रामकृष्ण पेदमपल्ली को मंडल संयोजक बनाया गया था। सरकार बदलते ही रामकृष्ण पेदमपल्ली को 18 जनवरी 2024 को मूल पद पर वापस भेज दिया गया। 18 जुलाई 2024 को छह माह हो गए।लेकिन पेदमपल्ली ने स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दी।फिर भी पेदमपल्ली को वेतन सामान रूप से मिल रहा है।ठीक ऐसा ही एक मामला भोपालपटनाम ब्लॉक में भी देखा गया है।जहां के एक शिक्षक बिना स्कूल गए वेतन लेकर अपना वजन बढ़ा रहे हैं।लेकिन ना ही अफसरों को इसकी भनक है, और ना ही किसी जिम्मेदार को चिंता।हर महीने करारे-करारे नोट इनके अकाउंट में गिर रहे हैं,तो फिर टेंशन कैसी।दबी जुबान में अब लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन शिक्षकों को अफसरों और नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है।

आपको बता दें कि बीजेपी शासनकाल में पुसबाका स्कूल को बंद किया गया था। शिक्षकों को दूसरे जगह मर्ज किया गया।लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो स्कूल दोबारा

खुला। पुसबाका स्कूल में एक प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक और शिक्षा दूत की पदस्थापना की गई। जिसके तहत प्रधान पाठक की जिम्मेदारी रामकृष्ण पेदमपल्ली को दी गई। लेकिन पदस्थापना के बाद भी प्रधान पाठक रामकृष्ण पेदमपल्ली ने ज्वाइनिंग नहीं दी।जिसका जीता जागता उदाहरण ये हाजिरी रजिस्टर है जिसमें रामकृष्ण पेदमपल्ली का नाम नहीं है।फिर भी पेदमपल्ली को पैसा मिल रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी संतोष गुप्ता को प्रधान पाठक रामकृष्ण पेदमपल्ली के छह माह तक गैरहाजिर रहने के बावजूद वेतन दिए जाने के संदर्भ में अवगत कराया गया तो संतोष गुप्ता ने कहा कि रामकृष्ण पेदमपल्ली ने ज्वाइनिंग दे दिया है। इसलिए उनका वेतन दिया जा रहा है।

खंड जिला शिक्षाधिकारी चाहे जो भी कहे लेकिन हाजिरी रजिस्टर झूठ नहीं बोलती।अब ऐसा सवाल है कि दैनंदिनी में हस्ताक्षर नहीं है ना ही सीएससी का वेतन प्रमाणीकरण नहीं है तो वेतन कैसे मिले?। स्कूलों के निरीक्षण में शिक्षा विभाग संकुल शिक्षकों की पदस्थापना करती है। संकुल शिक्षक स्कूलों का भ्रमण करते हैं फिर उपस्थित -अनुपस्थित की जानकारी समेत वेतन प्रमाण पत्र (पे-डाटा) देते हैं। इसके बाद ही शिक्षकों का वेतन क्लियर होता है। लेकिन प्रधान पाठक रामकृष्ण पेदमपल्ली के वेतन आहरण पंजी पर हस्ताक्षर ही नहीं है।तो फिर वेतन कैसे जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है।

बस्तर का बेटा नक्सलगढ़ के लोगों के लिए बना दूसरा भगवान

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का बस्तर हमेशा से ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जूझता रहा है। बस्तर में संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज खोला गया पर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी हमेशा बनी रही।लेकिन अब बस्तर का बेटा ही बस्तर के लोगों की मुश्किल दूर करने न्यूरोसर्जन बनकर अस्पताल आया है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जन के पद पर पदस्थ डॉक्टर का नाम पवन बृज है। वह सुकमा के बारसेरास गांव में पैदा हुए। प्रायमरी की पढ़ाई गांव में की। इसके बाद दंतेवाड़ा के मॉडल स्कूल में आगे की पढ़ाई की। बस्तर में लोगों को इलाज के लिए भटकते देख डॉक्टर बनने की सोची और इस राह पर चल पड़े। एमबीबीएस की पढ़ाई रायपुर के पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से की। मास्टर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई असम के डिब्रूगढ़ से की। कोर्स पूरा करने के बाद एमसीएच (सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन) रायपुर के डीकेएस पीजीआई से की। बस्तर का स्थानीय होने और यहां के लोगों को इलाज के लिए भटकते देखने के कारण शुरू से ही बस्तर के लोगों के इलाज का सपना देखा और इसी सपने को पूरा करने का उद्देश्य लेकर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी शुरू की। पवन बृज का सपना है कि मरीजों को बस्तर के बाहर जाकर इलाज के लिए ना भटकना पड़े। मेडिकल कॉलेज सह डिमरापाल अस्पताल में न्यूरोसर्जन की लगातार कमी चल रही थी। बस्तर में कोई भी न्यूरोसर्जन आना नहीं चाह रहे थे। ऐसे में बस्तर में लगातार होने वाले सड़क हादसे से लेकर दिमाग मे जमने वाले खून के थक्के को निकालने के लिए मरीजों को रायपुर या फिर विशाखापत्तनम जाना पड़ता था। कुछ दिनों पहले बस्तर के डिमरापाल अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर पवन बृज की नियुक्ति की गई। उनके आने के बाद से ही सप्ताहभर में छह मरीजों की न्यूरोसर्जरी की।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ज्वालेश्वर महादेव की महिमा क्षण मात्र में मिट जाते हैं पाप

गौरेला पेंड्रा मरवाही। सावन के पवित्र माह में अमरकंटक तीर्थ स्थल भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है।ऊंचे पहाड़ पर नर्मदा उद्गम स्थल पर शिवभक्तों की भीड़ लगती है।इस बार भी अमरकंटक आने वाले शिवभक्तों ने तैयारी की है। सावन के दूसरे सोमवार को ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी। जय माता ज्वालाधाम गिरारी से जुड़े सैकड़ों शिवभक्त पदयात्रा करते हुए गिरारी से पेंड्रा पहुंचे। इसके बाद सभी वाहनों से मध्यप्रदेश के अमरकंटक रवाना हुए। जहां से पैदल नर्मदा जल लेकर छत्तीसगढ़ के ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। शिव भक्ति में लीन सभी भक्त भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए पेंड्रा से रवाना हुए हैं। सावन के दूसरे सोमवार को पेंड्रा के गिरारी गांव स्थित जय माता ज्वालाधाम के सैकड़ों श्रद्धालु आज गिरारी गांव से पैदल भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए पेंड्रा पहुंचे। जहां से सभी वाहनों में सवार होकर अमरकंटक रवाना हुए हैं। ये सभी श्रद्धालु स्वयंभू ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।

खराब सड़क पर परिवार समेत गिरा आरक्षक, पैर फैक्चर

जगदलपुर। जगदलपुर शहर के अपराधों को रोकने के साथ ही नक्सलियों से डटकर मुकाबला करने वाले जवानों को खुद को सुरक्षित रखना काफी मुश्किल हो गया है। इन जवानों के लिए बनाए गए सरकारी आवास तो मिल गए, लेकिन आने वाले मार्ग में अब तक सड़क निर्माण नही हो पाया। जिसके चलते बरसात के दिनों में इन जवानों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, ऐसे में रविवार को एक जवान अपने परिवार समेत बाइक से गिर गया, जिससे कि उसका पैर भी फैक्चर हो गया, साथ ही बाइक में बैठे बच्चा और पत्नी सुरक्षित थे, घायल को बेहतर उपचार के लिए मेकाज में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि परपा में पुलिस जवानों के लिए सरकारी आवास का निर्माण 7 वर्षों पहले कराया गया था, इस आवास में करीब 4 सौ के लगभग परिवार निवास करते है, लेकिन इन परिवार के लोगों को बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण है कि वह डामर सड़क नही है, वहां केवल मिट्टी को बिछा दिया गया है।

प्रत्येक शुक्रवार को समूह के उत्पाद का काउंटर लगेगा

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा महिलाओ को रोजगारमुखी बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्व-सहायता समूह द्वारा बनाये जा रहे शुद्ध, नेचुरल, स्वास्थ्य वर्धक घरेलू उत्पादो को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में जनगणना विभाग के बगल में जगह निर्धारित किया गया है। जहां पर प्रत्येक शुक्रवार को स्व-सहायता समूह की बहनो द्वारा अपने-अपने उत्पाद को लाकर कार्यलयीन अवधि में विक्रय किया जाएगा। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने लोगो से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में स्व-सहायता समूह द्वारा बनाये गये उत्पाद को खरीदें। जिससे सबको प्रोत्साहन मिले, शहरी अजीविका मिशन का लक्ष्य है, महिला समूहो को स्वालम्बी बनाना। स्वच्छता समूह के महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे प्रमुख रूप से उत्पाद रहेगा - आंवले का मुरब्बा, आंवला जूस, आचार, पापड़, बड़ी, जुट बैग, नेचुरल खाद, मिट्टी भरकर पौधा लगाने वाले बैग, सजावटी सामान, आगरबत्ती, धुप बत्ती का विक्रय किया जायेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 8 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

महासमुंद। एकीकृत बाल विकास परियोजना पिथौरा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत पिथौरा के वार्ड क्रमांक 04 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति की जाएगी। आवश्यक अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका 08 अगस्त 2024 तक अपना आवेदन आवश्यक वैद्य एवं स्व-प्रमाणित दस्तावेजों के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय पिथौरा में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है या पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केन्द्र जिस वार्ड में स्थित है, आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का पद पूर्णत: मानसेवी तथा अशासकीय पद हैं।

मवेशी को बचाने के चक्कर में बाइक सवार की गई जान

जगदलपुर। बस्तर जिले के दो अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में दो लोगों को अपनी जान गवांनी पड़ी वहीं एक युवक घायल हो गया। जिसे 108 की मदद से मेकाज में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहने वाले ऋषभ शर्मा अपने दोस्त धनराज को लेकर बुलेट वाहन में 27 जुलाई को जैबैल गए हुए थे। जहाँ से काम खत्म कर वापस 28 को अपने घर जगदलपुर आ रहे थे कि छोटे देवड़ा और डोडरेपाल के पास अचानक से मवेशियों का झुंड आने से उसे बचाने के चक्कर मे गिर पड़े। जिसके बाद घायलों को 108 की मदद से पहले महारानी अस्पताल ले जाया गया जहां से घायलों को मेकाज लाया गया जहाँ उपचार के दौरान ऋषभ की मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त का अब भी उपचार चला रहा है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही परिजनों का हॉस्पिटल आना शुरू हो गया।

धड़ल्ले से चल रहा है सट्टे का कारोबार, रोजाना लग रहे है लाखों के दांव

कांकेर। कांकेर जिले में जुएं सट्टे का कारोबार जोरों पर है। हर गांव मोहल्ले में रोजाना नए खईवालों के तादात में इजाफा हो रहा है,अपराधों को रोकने वाले पुलिस के हथकंडे फेल होने से सट्टाबाजों का हौसले बुलंद है। अलाम ये है की इसके चुंगुल में सबसे ज्यादा युवाओं का भविष्य तबाह हो रहे है और सट्टेबाज इस कारोबार से लाखों कमा रहे है। जिले में चल रहे अवैध जुआ सट्टा कारोबार की बात कि जाए तो जिले में नासूर की तरह फैला चुका ये अवैध कारोबार कोरर सहित चारामा इलाके में बेधडक संचालित है और स्थानीय पुलिस इस कारोबार से बेखबर है या सट्टेबाज को संरक्षण दे रही है ये सवालिया निशान है।

कोरर और चारामा इलाके में चल रहे सट्टा कारोबार की बात की जाए तो इस कारोबार में रोजाना कारोबार लाखों दाव खाईवाल घर बैठे मोबाईल से संचालित करर रहे हैं और सट्टे में हार जीत का दांव

लगाने अपनी गाढ़ी कमाई इस खेल में गंवाकर बर्बाद हो रहे हैं। जिले के कई इलाकों में चल रहे अवैध जुआ सट्टा के कारोबार पर पुलिसिया आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक़ जनवरी से जून माह तक जुआ मामले में कुल 13 प्रकरण दर्ज 15 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर 55,990 रूपये जब्त किया गया और वही सट्टा के 22 प्रकरण 81 लोग के विरुद्ध कार्यवाही कर 1,41,680 रूपये बरामद हुए है जुआ और सट्टा के आंकड़ों से ही साफ़ है की सट्टा का कारोबार कैसे बेधड़क संचालित हो रहा है और रोकने वाले छोटे मोटे सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई कर अपने डायरी मेंटेन किया जा रहा है। नये अपराध को रोकने व् पुराने मामलों के निबटारा के लिए पुलिस विभाग के आला अफसर हर माह में एक बार तो तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की बैठककर छोटे बड़े अपराधों पे जानकारी लेते है जिसमें नक्सल मसले के साथ अन्य अपराधों पर भी आला अफसर अपराधों को रोकने के भी निर्देश देते है लेकिन जिस तरह जुआ और सट्टा का कारोबार संचालित हो रहे है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कनिष्ट पुलिस अधिकारी कही ना कही उन आदेश निर्देशों को अनदेखा कर रहे है और नतीजा ये है की जुआ सट्टा के कारोबार में इजाफा हो रहा है और सट्टेबाजों को इसका भरपूर मुनाफ़ा मिल रहा है। जैसे जैसे बस्तर पुलिस आधुनिक हो रही है वैसे वैसे इस अवैध कारोबार से जुड़े खाईवाल और सटोरी भी हाईटेक हो चुके है अब सट्टे का कारोबार कागज कमल की जगह मोबाईल और एप्लीकेशन से संचालित होते है बीते मई महीने में स्वस्तिक और बेटओनली एप से आईपीएल में खुलेआम सट्टा का कारोबार जिले में चलता रहा मीडिया ने भी जमकर सट्टे के कारोबार पर मामला उजागर किया और पुलिस ने कार्यवाही का दावा किया लेकिन आईपीएल मैच खत्म भी होगा लेकिन नगर का हाईटेक खाईवाल आज भी कानून की गिरफ्त से बाहर है

प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तब महादेव सट्टा एप को लेकर भाजपा ने जमकर मौजूदा सरकार पर हमला किया लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद आज जब भाजपा राज में सट्टे का कारोबार जोर पर है तो विपक्ष पुरी तरह हो इस सामजिक बुराई पर किसी तरह का अपना विरोध दर्ज तक नहीं करा पा रही है अब सवाल सीधा है इस अवैध कारोबार पर कैसे लगाम लग पायेगा।

सावन के दूसरे सोमवार पर महिलाओं की अनोखी भक्ति

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। सावन के पवित्र महीने में देवालयों में शिवभक्तों का तांता लगा हुआ है।सुबह से लेकर शाम तक भक्त महादेव की आराधना में लीन हैं।ऐसा माना जाता है कि सावन के माह में शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।इसलिए भक्त सावन के महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक करके उन्हें प्रसन्न करते हैं।इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़ के प्राचीन श्री संकट मोचन मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को महिलाओं ने सामूहिक रूप से जलाभिषेक किया।

इस मौके पर सभी महिला शिव भक्तों ने मंदिर से जल भरकर नाकेश्वर महादेव मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकाली। जिनमें महिलाओं की भक्ति और उत्साह की झलक देखते ही बनती थी। यह धार्मिक कार्यक्रम सुबह से ही प्रारंभ हुआ, जहां महिलाओं ने मंदिर में पूजा-अर्चना की फिर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सभी महिला श्रद्धालुओं ने मिलकर नाकेश्वर महादेव मंदिर में सामूहिक रूप से जलाभिषेक किया।

इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने

शिव भक्तों के संगठित होकर इस तरह के धार्मिक आयोजनों को उत्साहपूर्वक मनाने का संदेश दिया। सावन के महीने में पार्थिव शिव पूजन का विशेष महत्व है। यही वजह है कि शिव भक्त इन दिनों घर-घर भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनवाकर पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो वहीं शहर के वार्ड क्रमांक 12 स्थित संकट मोचन मंदिर भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में जमा हुए। आपको बता दें कि सीएमओ बंगला के सामने शहर का प्राचीन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर स्थित है। मंदिर परिसर में ही विशालकाय पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान शिव की मूर्ति विराजित है।

संक्षिप्त समाचार

सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में विशेष श्रृंगार

रायपुर। लगातार बारिश के बीच सावन के दूसरे सोमवार पर राजधानी के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया गया है। शिवालयों में सुबह से ही महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी लाइन लगी है। चारों तरफ जयकारें लग रहे हैं। श्रद्धालु जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, भस्म आदि से पूजा कर रहे हैं। रायपुर के प्राचीन हटकेश्नवरनाथ महादेव ,बूढ़ेश्वर महादेव में विशेष श्रृंगार किया गया है।

मुख्यमंत्री साय मिले केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री चौहान से

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव

साय ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।

कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिन्दल को महात्मा हंसराज गौरव सम्मान

रायपुर। नई दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज

कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस समारोह में कुरुक्षेत्र के सांसद और देश के अग्रणी उद्योगपति नवीन जिन्दल को महात्मा हंसराज गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए लंबा कानूनी संघर्ष करने और उसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए नवीन जिन्दल के अथक प्रयासों की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंच से भरपूर तारीफ की। राजनीति, उद्योग, शिक्षा जगत और पोलो, निशानेबाजी जैसे खेलों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिन्दल को हंसराज कॉलेज ने दो दिन पूर्व अपने 77वें स्थापना दिवस पर खास मेहमान के रूप में आमंत्रित किया था। जिन्दल ने इसी कॉलेज से कॉमर्स में डिग्री हासिल की है। अपने इस होनहार छात्र की उपलब्धियों को देखते हुए हंसराज कॉलेज ने नवीन जिन्दल को महात्मा हंसराज गौरव सम्मान से अलंकृत किया। यह सम्मान उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह और हंसराज कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रमा ने प्रदान किया।

महापौर ढेबर ने रायपुर एसएसपी को दी आत्महत्या की धमकी

रायुपर। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस

से बदसलूकी के आरोप में महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में को महापौर ढेबर ने सोमवार को रायपुर एसएसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन में मौजूद 25000 हजार लोगों पर एफआईआर करने कहा या फिर एफआईआर को शून्य करने की मांग करते हुए आत्महत्या की धमकी भी दी। इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, एमआईसी सदस्य समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एफआईआर के मुताबिक, 24 जुलाई को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शासन के विरुद्ध विभिन्न मुद्दों को लेकर बिना अनुमति के विधानसभा घेराव करने करने के लिए निकले थे। इस दौरान साहू फर्निचर बैरिकेडिंग नंबर 2 विधानसभा के पास रास्ता बाधित किया गया था। महापौर एजाज ढेबर, आशीष द्विवेदी एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस बल के साथ गाली गलौज, झूमा झटकी कर मारपीट की थी। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

राज्यपाल से विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से

सोमवार को राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने सौजन्य भेंट कर उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार पात्रा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला एवं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर बलदेव शर्मा उपस्थित थे।

महिलाओं को न्याय दिलाने में सभी सदस्यों का हमेशा सहयोग रहा : किरणमयी नायक

आयोग ने सदस्यों को विदाई समारोह में किया सम्मानित

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य श्रीमती नीता विश्वकर्मा (सरगुजा), श्रीमती अर्चना उपाध्याय (कोरबा) एवं श्रीमती बालो बघेल (बस्तर) का कार्यकाल पूरा हुआ। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी जिसमें श्रीमती राठौर की कार्यकाल के दौरान स्वर्गवास हो गया था एवं डॉ. अनिता रावटे ने 2 माह पूर्व इस्तीफा दे दिया था। बाकी तीनों सदस्यों ने अपना कार्यकाल 27 जुलाई को पूर्ण किया।

ज्ञात हो कि पांचो सदस्यों ने 27 जुलाई 2021 को आयोग में पदभार ग्रहण किया था। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के निर्देश पर आयोग द्वारा सदस्यों की विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन आयोग मुख्यालय में किया गया। कार्यक्रम की शुरूवात करते हुये अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा सदस्य श्रीमती नीता विश्वकर्मा (सरगुजा), श्रीमती अर्चना उपाध्याय (कोरबा) एवं श्रीमती बालो बघेल (बस्तर) का मेमेन्टो श्रीफल एवं शाल द्वारा सम्मानित किया गया। जिसमें आयोग के सदस्य सचिव मनोज कुमार, सहायक संचालिका श्रीमती पुष्पा किरण कुजूर एवं समस्त कर्मचारीगण उपस्थित थे।

उपस्थितजनों को संबोधित करते हुये अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि उनकी नियुक्ति के 1 वर्ष पश्चात् पांचो सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के पहले अध्यक्ष द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री छ.ग. शासन से विशेष निवेदन किया गया था कि सभी संभागों से सदस्यों की नियुक्तियां की जाय ताकि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने में तथा सभी क्षेत्रों में आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में आयोग को सहयोग मिलता रहे। फलस्वरूप लगभग सभी संभागों के अन्तर्गत सदस्यों की नियुक्ति हुई थी खास करके बस्तर और सरगुजा संभाग को विशेष ध्यान रखते हुये नियुक्ति की गई थी। अंत में अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये कहा कि आयोग के कार्यों में एवं महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाने में आप सभी का अनुभव की वजह से ही हमने हजारों की संख्या में महिलाओं को उनका अधिकार दिला पाये। हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी आप सभी के अनुभव का आयोग को सहयोग मिलता रहे।

सदस्य श्रीमती नीता विश्वकर्मा ने कहा कि जब हम किसी परिवार से जुडते है तो उनसे अलग होने में तकलीफ होती है यह 3 वर्ष कब समाप्त हुआ पता ही नहीं चला। अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के साथ इस 3 वर्ष में बहुत कुछ सीखने को मिला। सदस्य के रूप में भले ही यह मेरा आखरी दिन है मगर महिलाओं को न्याय दिलाने में आगे भी कार्य करते रहेंगे।सदस्य श्रीमती बालो बघेल ने कहा कि मैं बस्तर संभाग की एक छोटे से गांव से आती हूं मुझे डॉ. किरणमयी नायक की वजह से महिलाओं को न्याय दिलाने का अवसर प्राप्त हुआ जिसके लिए मैं अध्यक्ष की आभारी हूँ।

बिजली के दाम बढ़ाने पर प्रदेशभर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

रायपुर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने आज सभी विधानसभा में बिजली बिल जलाओ आंदोलन चलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में बूढ़ा तालाब स्थित बिजली ऑफिस में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगी बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल में बढ़ोतरी कम करो के नारे लगाए।

बिजली बिल का दर बढ़ाने और स्मार्ट मीटर के विरोध में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और विष्णु देव साय मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल को जलाया और उसके बाद बिजली ऑफिस के अधिकारियों को उसका राख भेंट किया। साथ ही राख को लिफाफा में बंद कर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को देने की बात कही।

प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ की आम जनता परेशान है। आज युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में बिजली ऑफिस में बिजली बिल जलाओ आंदोलन चलाया। पिछले कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल हाफ हाफ योजना का लाभी मिलता था। आज भाजपा सरकार बिजली बिल में बढ़ोतरी कर आम जनता के जेब में डाका डालने का काम कर रही है। जिसके घर में पहले ?1000 से 2000 तक की बिजली बिल आती थी आज उनके यहां 4000 से 5000 तक की बिजली बिल आ रहे हैं। इसे लेकर आज आम जनता में बहुत आक्रोश है। आम जनता ने अपना बढ़ा बिजली बिल को हमें दिया है और हम आज 90 विधानसभा में

आंदोलन कर रहे हैं।

शर्मा ने कहा, आज हमने बिजली के बिल को बिजली ऑफिस के सामने जलाया और अधिकारियों को जला हुआ राख प्रदान किया। साथ में हमने बिजली बिल के जले हुए राख एक लिफाफा में इकट्ठा किया है और पूरे 90 विधानसभा में जो आज आंदोलन हो रहा है वहां से भी हम जले हुए बिजली बिल को मंगवाएंगे और लिफाफे में भरकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भेंट करेंगे। सीएम से मांग करेंगे कि बिजली बिल की दरों को काम किया जाए। यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। यह शुरुआत है। आने वाले समय में भी हम बिजली बिल को लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे।

प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, पीसीसी महासचिव दीपक मिश्रा, सकलेन मुश्तक, शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे, युवा कांग्रेस महासचिव भावेश शुक्ला, ह्रस्ट्ड प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा, जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप, विधानसभा अध्यक्ष समीर भट्ट, प्रदेश संयोजक तुषार गुहा, प्रदेश सचिव अभिषेक कसर, रुचिर दुबे, आशुतोष मिश्रा, दीपक मिश्रा, लक्षित तिवारी, प्रतीक शर्मा, शुभम दुबे आदि शामिल थे।

साय की पहल से सरगुजा संभाग को मिली 15 विशेषज्ञ चिकित्सकों की सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अनुशंसा पर सरगुजा संभाग में पंद्रह विशेषज्ञ चिकित्सकों (एनएचएम संविदा) की पोस्टिंग का आदेश जारी हो गया है। इन चिकित्सकों के मिल जाने से संभाग में त्वरित एवं बेहतर उपचार की बड़ी सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी किये गए आदेश में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकेश कुमार पटेल को जिला अस्पताल (एस.एन.सीयू.) जिला जशपुर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ब्राडिना छाया नायक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी (एफ.आर.यू) जिला जशपुर, एम.डी. मेडिसीन डॉ. पियुष देवांगन को जिला अस्पताल, जिला जशपुर, शल्यक्रिया विशेषज्ञ डॉ. शरद मनीष गरेवाल को जिला अस्पताल, जिला जशपुर, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. मनीष कुमार ध्रुव को जिला अस्पताल, जिला जशपुर पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहनीश खत्री को जिला अस्पताल, जिला जशपुर, रेशपेरेटरी मेडिसीन डॉ. कमल नारायण गुप्ता को जिला अस्पताल, जिला जशपुर, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. कलिन्दर सिंह पैको को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-चिरमिरी (एफ.आर.यू.), जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल मोकासदर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.)-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पूजा प्रजापति को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.)-मनेन्द्रगढ़, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, एम.डी. मेडिसीन डॉ. शीतल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.)- चिरमिरी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. केदारनाथ देवांगन को जिला अस्पताल, जिला-कोरिया, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. दीपांकर साहू को जिला अस्पताल, जिला-कोरिया, स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. बेबी प्रज्ञा श्री ओझा को जिला अस्पताल, जिला-कोरिया, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना अय्यर को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, जिला-सरगुजा छत्तीसगढ़ में पदस्थ किया गया है।

जुआ एक्ट में अब एसीबी एवं ईओडब्ल्यू को मिला जांच और कार्रवाई का अधिकार

■ **ऑनलाइन जुआ-सट्टा के मामलों में तेजी से होगी प्रभावी कार्रवाई**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य में जुआ-सट्टा विशेषकर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कड़ाई से रोक और इस मामले में संलिप्त लोगों पर तेजी से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विधिवत् अधिसूचना का प्रकाशन कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की समस्त धाराओं के अंतर्गत अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) को जांच और कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू को यह अधिकार मिलने से ऑनलाइन जुआ के मामलों में भी तेजी से जांच एवं प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू अब तक केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों में जांच करती रही है। इस अधिसूचना के प्रकाशन से एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच और कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। गौरतलब है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू को जुआ एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई का अधिकार मिलने से इन मामलों की जांच एक ही विंग में होगी। जिससे जांच में आसानी और कार्रवाई में तेजी आएगी। राज्य में जुआ-सट्टा पर प्रभावी तरीके से शिकंजा कसा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम में ऑनलाइन जुए को शामिल किया गया है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान तथा गैर जमानती धाराओं को शामिल किया गया था। अधिनियम में कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान करते हुए जुआ घर का स्वामी होना, जुआ खिलाना, ऑनलाइन जुआ खिलाना, विज्ञापन प्रतिषेध का उल्लंघन और कंपनी द्वारा अपराध को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध बनाया गया है। छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 में जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्म शब्द जोड़ा गया है। उपकरण की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डिवाइस, मोबाइल एप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स शब्द जोड़े गये हैं। पुराने अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं था। अब पृथक से दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की जेल एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक जेल और 10 लाख तक का जुर्माने हो सकता है।

नवनियुक्त नगरीय निकाय कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में नवनियुक्त नगरीय निकाय कर्मचारी संघ ने सरकार से अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को सीएम साय के नाम ज्ञापन सौंपा है। नवनियुक्त कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रसुन्न शर्मा ने बताया कि हमारी दो सूत्रीय मांग है, जो सरकार तुरंत पूरा कर सकती है। इसमें पहली मांग है कि हमें नियमित भुगतान किया जाए। वर्तमान में हमें तीन-चार महीनों तक वेतन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके।

उन्होंने कहा कि हम सुबह से लेकर रात तक सफाई अभियान में लगे रहते हैं, लेकिन हमें नियमित वेतनमान नहीं मिलता है, जो सही नहीं है। अपनी मांगों को लेकर हमने इससे पहले काली पट्टी लगाकर एक दिवसीय 'काम बंद, कलम बंद' हड़ताल किया था। आज एक दिवसीय प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है।

चेन पुलिंग पर आरपीएफ ने 24 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई

■ **ट्रेनों में अलार्म चेन का दुरुपयोग न करें, यात्रियों से रेलवे की अपील**

रायपुर। बिना ठोस कारण के ट्रेन में चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तथा चेन पुलिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया।

रायपुर डिवीजन् में रेल यात्रियों द्वारा ट्रेन में लगातार की जा रहे चेन पुलिंग कि शिकायत पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, रायपुर, श्री रमन कुमार द्वारा आर पी एफ कि टीम बनाकर रेलवे स्टेशन भिलाई पावर हाउस में कार्यवाही करने हेतु आदेश किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा ट्रेन नंबर 18202 नवतनवा ङ्क दुर्ग में बिना उचित कारण के चेन खिंचने वाले लोगो पर कार्यवाही की गई।

ट्रेन श्रु पास होते ही चेन पुलिंग हॉर्न के कारण रूक गई तुरंत वहाँ पर मौजूद आर पी एफ के अधिकारी व बल सदस्य हरकत में आ गए एवं उक्त ट्रेन से उतरे हुए यात्रियों को रोक कर उनसे बिना स्टॉपेज के भिलाई पावरहाउस में उतरने का कारण पूछा। टीटीई द्वारा यात्रियों का टिकट चेक करने पर पाया गया कि अधिकांश यात्री दुर्ग तक यात्रा करने का टिकट रखे हैं परन्तु चेन खींच कर भिलाई पावर हाउस में उतर गए। पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं होने के कारण चेन खिंचने वाले 1 व्यक्ति को रेलवे एक्ट कि धारा 141 के तहत गिरफ्तार किया। उनमे से 6 यात्रियों को रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत गिरफ्तारी, 10 व्यक्तियों को रेलवे एक्ट की धारा 145 बी के तहत गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। सात व्यक्तियों से टीटी के माध्यम से रू1640 जुर्माना वसूला गया। कुल 24 यात्रियों पर समस्त क़ानूनी कार्यवाही कर चेतावनी देकर मुचलका पर छोडा गया।

राज्यपाल हरिचंदन ने किया छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस इकाई की स्मारिका का विमोचन

■ **राज्य रेडक्रॉस इकाई ने राज्यपाल को किया सम्मानित**

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में रेडक्रॉस समिति छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023-24 की स्मारिका का विमोचन किया।

इस अवसर पर रेडक्रॉस समिति छत्तीसगढ़ के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री एम.के.राउत ने संस्था के राज्य संरक्षक राज्यपाल श्री हरिचंदन के कार्यकाल के दौरान रेडक्रॉस की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रेडक्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक को अत्याधुनिक बनाने के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस निर्माण के लिए राज्यपाल ने स्वेच्छानुदान मद से 72 लाख रूपए प्रदान किए। राज्यपाल के निर्देश पर आकस्मिक स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए शासकीय चिकित्सकों को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा राज्य के सभी जिलों में गांव-गांव में प्राथमिक चिकित्सा सहायता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्री हरिचंदन की पहल पर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा अपने कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सी.एस.आर.) मद से 50 लाख की राशि रेडक्रॉस को प्रदान की गई है। साथ ही केन्द्र सरकार की संस्था ग्रामीण विद्युत कॉर्पोरेशन द्वारा 4 करोड़ 83 लाख की लागत के चार मेडिकल मोबाईल यूनिट (एम्बुलेंस) आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। रेडक्रॉस समिति के पदाधिकारियों ने इसके लिए श्री हरिचंदन का आभार माना। संस्था की ओर से राज्यपाल को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रेडक्रॉस समिति छत्तीसगढ़ के चेयरमेन श्री अशोक अग्रवाल, सचिव डॉ. रूपल पुरोहित, डॉ.एस.एन पाण्डेय एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 2 (छत्तीसगढ़)
ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

(प्रथम आमंत्रण)

दिनांक 25.07.20284

निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा डी श्रेणी एवं अधिक श्रेणी के ठेकेदारों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 13.08.2024 है।

एन.आई.टी क्रं. निविदा क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रु.)
1	2	3
NIT NO. 306 Tender No. 156627	जिला महासमुंद के उपसंभाग क्रंमाक-1 महासमुंद के अंतर्गत शासकीय गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य।	रु. 40.00 लाख
NIT NO. 307 Tender No. 156628	जिला महासमुंद के उपसंभाग क्रंमाक-1 महासमुंद के अंतर्गत शासकीय आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य।	रु. 30.00 लाख
NIT NO. 308 Tender No. 156629	जिला महासमुंद के उपसंभाग क्रंमाक-2 महासमुंद के अंतर्गत शासकीय गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य।	रु. 50.00 लाख
NIT NO. 309 Tender No. 156631	जिला महासमुंद के उपसंभाग क्रंमाक 2 महासमुंद के अंतर्गत शासकीय आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य।	रू. 30.00 लाख
NIT NO. 310 Tender No. 156632	गरियाबंद अनुविभाग क्रं.02 के अंतर्गत देवभोग उपखण्ड के गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत कार्य।	रु. 30.00 लाख
NIT NO. 311 Tender No. 156633	गरियाबंद अनुविभाग क्रं.02 के अंतर्गत मैनपुर उपखण्ड के गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत कार्य।	रु. 30.00 लाख
NIT NO. 312 Tender No. 156635	गरियाबंद अनुविभाग क्रमांक 02 के अंतर्गत मैनपुर उपखण्ड के आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत कार्य।	रू. 22.00 लाख
NIT NO. 313 Tender No. 156636	जिला महासमुंद के उपसंभाग पिथौरा अंतर्गत शासकीय आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य।	रु. 40.00 लाख
NIT NO. 314 Tender No. 156637	जिला महासमुंद के उपसंभाग पिथौरा अंतर्गत शासकीय गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य।	रु. 50.00 लाख
NIT NO. 315 Tender No. 156638	राजिम अनुविभाग के अंतर्गत राजिम एवं फिंगेश्वर उपखण्ड के गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत कार्य।	रु. 30.00 लाख
NIT NO. 316 Tender No. 156639	राजिम अनुविभाग के अंतर्गत पाण्डुका एवं छुरा उपखण्ड के आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत कार्य।	रू. 25.00 लाख
NIT NO. 317 Tender No. 156640	राजिम अनुविभाग के अंतर्गत राजिम एवं फिंगेश्वर उपखण्ड के आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत कार्य।	रू. 25.00 लाख
NIT NO. 318 Tender No. 156642	राजिम अनुविभाग के अंतर्गत पाण्डुका एवं छुरा उपखण्ड के गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत कार्य।	रु. 30.00 लाख
NIT NO. 319 Tender No. 156643	जिला महासमुंद के उपसंभाग सरायपाली अंतर्गत शासकीय आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य।	रू. 40.00 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट बेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। (राशि रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र एवं न्यूनतम राशि रू. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम पर एनेक्जर-3 का शपथ पत्र बिडकेपेसीटी उपलब्धता बाबत् जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईटी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रपत्रानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि. रायपुर मंडल
क्रमांक-2 (छ.ग.)

जी- 242501390/7 Credible Chhattisgarh विश्वसनीय छत्तीसगढ़ आपकी थी चाह, हमने बनाई राह

क्या 2 विदेशी मुल्कों में जंग खत्म करवा पाएगा हिंदुस्तान?

अभिनय आकाश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे और व्लादिमीर पुतिन को गले लगाती तस्वीर तो आपको याद ही होगी। जिस तस्वीर को देखकर रूस के कट्टर दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलदोमीर जेलेंस्की भड़क गए थे। लेकिन अब पुतिन के बाद पीएम मोदी की जेलेंस्की के साथ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आने वाली है। जी हां, पीएम मोदी अब यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। जाहिर है यूक्रेन दौरे के दौरान पीएम मोदी की मुलाकात वोलादमीर जेलेंस्की से होगी। ये भी जाहिर है कि जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का मसला भी उठेगा। ऐसे में भारत एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने और शांति बनाए रखने की अपील कर सकता है। आपको याद हो कि पीएम मोदी हाल ही में रूस के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। यूक्रेन से युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की थी। अब पीएम मोदी के यूक्रेन जाने की बात सामने आई है। अगर ऐसा होता है तो रूस यूक्रेन जंग के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला कीव दौरा रहेगा। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो चली है कि क्या जंग खत्म करवाने में भारत मध्यस्थ बनेगा। क्या दोनों मुल्कों के बीच जंग खत्म कराने के मिशन में भारत कामयाब हो पाएगा। नई दिल्ली का कीव से पुराना नाता है। भारत यूक्रेन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। जनवरी 1992 में दोनों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। सोवियत काल से पहले और बाद में दोनों देशों ने साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। भारत और यूक्रेन के बीच सहयोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कृषि व्यापार ने भारत और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों का आधार बनाया। कीव ने 2021 में .2 बिलियन से अधिक मूल्य का निर्यात किया। हालाँकि, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है। 2022 में भारत-यूक्रेन व्यापार की मात्रा एक साल पहले के 3.38 बिलियन डॉलर से घटकर 2.58 बिलियन डॉलर हो गई। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, जहां यूक्रेन को भारत का निर्यात 22.8 प्रतिशत घटकर 85.49 मिलियन डॉलर हो गया, वहीं भारत को यूक्रेन का निर्यात 17.3 प्रतिशत गिरकर 1.69 बिलियन डॉलर हो गया।

भारत और यूक्रेन के संबंध सांस्कृतिक आदान-प्रदान से भी विकसित होते हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, यूक्रेन में जनता को भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि है, जिसमें इसके नृत्य, योग, दर्शन, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता शामिल हैं। 30 से अधिक यूक्रेनी सांस्कृतिक संघ और समूह हैं जो भारतीय कलाओं, विशेषकर नृत्यों को बढ़ावा देते हैं। यूक्रेन एक छोटे भारतीय समुदाय की भी मेजबानी करता है, जिसमें मुख्य रूप से व्यावसायिक पेशेवर और छात्र शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, व्यापारिक समुदाय यूक्रेन में विनिर्माण, पैकेजिंग, व्यापार और सेवा उद्योग में शामिल है। यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध पर नई दिल्ली तटस्थ बनी हुई है। भारत मास्को के साथ ऐतिहासिक संबंध साझा करता है, जो उसका शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत एक अनोखी स्थिति में है क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों उसके प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं। जबकि नई दिल्ली ने युद्ध पर पुतिन की आलोचना करने से परहेज किया है, इसने संघर्ष को समाप्त करने के लिए बार-बार कूटनीति और बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति प्रयासों में योगदान देने की भी पेशकश की है। भारत ने मास्को के साथ अपने संबंध बनाए रखने के लिए पश्चिम के दबाव का विरोध किया है। इस महीने की शुरुआत में, पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर रूस गए, यूक्रेन युद्ध के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बैठक में भारतीय नेता ने कहा था कि भारत ने हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने का आह्वान किया है। युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं है. बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यूक्रेन ने कीव के शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड सम्मेलन में भारत की भागीदारी की मांग की थी। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) पवन कपूर ने शांति शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। हालाँकि, भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच ईमानदार और व्यावहारिक जुड़ाव का आह्वान किया था।

लोकसभा अध्यक्ष विवादों में क्यों

विनीत नारायण

भारतीय लोकतंत्र की परंपरा काफी सराहनीय रही है। लोकसभा भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है जहां देश के कोने-कोने से आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र, प्रांत व राष्ट्र के हित में समस्याओं पर विमर्श करते हैं। लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नोक-झोंक का चलना बहुत सामान्य व स्वाभाविक बात है। सत्तापक्ष अपनी छवि बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता है तो विपक्ष उसे आईना दिखाने का काम करता है। इससे मुद्दों पर वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। इस नोक-झोंक का कोई बुरा नहीं मानता क्योंकि आज जो सत्ता में हैं, कल तक वह विपक्ष में थे और तब वे भी यही करते थे जो आज विपक्ष कर रहा है। जो आज सत्ता में हैं कल वह विपक्ष में होंगे और फिर वे भी वही करेंगे। लेकिन इस नोक-झोंक की सार्थकता तभी है जब वक्ताओं द्वारा मर्यादा में रह कर अपनी बात रखी जाए।

जब तक संसदीय कार्रवाई का टी.वी. पर प्रसारण नहीं होता था, तब तक देश की जनता को यह पता ही नहीं चलता था कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में कैसा व्यवहार कर रहे हैं? उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि वे संसद में किन मुद्दों को उठा रहे हैं? अक्सर ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब सांसदों ने आर्थिक लाभ की एवज में बड़े औद्योगिक घरानों के हित में सवाल पूछे। वरिष्ठ पत्रकार ए. सूर्यप्रकाश ने 30 वर्ष पहले ऐसे लेखों की शृंखला छापी थी जिसमें सांसदों के ऐसे आचरण का खुलासा हुआ और देश ने पहली बार जाना कि 'संसद में सवाल बिकते हैं'। पर जब से टी.वी. पर संसदीय कार्रवाई का प्रसारण होने लगा तब से आम देशवासियों को भी ये देखने को मिला कि हमारे सांसद सदन में कैसा व्यवहार करते हैं। बिना अतिशयोक्ति

के यह कहा जा सकता है कि प्राय: कुछ सांसद जिस भाषा का प्रयोग आजकल करने लगे हैं उसने शालीनता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। शोर-शराबा तो अब आम बात हो गई है। ऐसा नहीं है कि संसद में ये हुड़दंग केवल भारत में ही देखने को मिलता है।

यूरोप सहित दुनिया के अनेक देशों से ऐसे वीडियो आते रहते हैं, जिनमें सांसद हाथापाई करने और एक-दूसरे पर कुर्सियां और माइक फैंकने तक में संकोच नहीं करते। सोचिए इसका देश के बच्चों और युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? सोचने वाली बात यह भी है कि संसद की कार्रवाई पर इस देश की गरीब जनता का अरबों रुपया खर्च होता है। एक आंकलन के अनुसार संसद चलने का प्रति मिनट खर्च अढ़ाई लाख रुपए से थोड़ा अधिक आता है। इसका सदुपयोग तब हो जब गंभीर चर्चा करके जनता की समस्याओं के हल निकाले जाएं। जिस तरह एक विद्यालय में शिक्षक कक्षा के सक्षम और योग्य छात्र को क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, जिससे वह कक्षा में अनुशासन रख सके। उसी तरह लोकसभा के सांसद भी अपना मॉनिटर चुनते हैं जो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। आज तक हमारी लोकसभा का यह इतिहास रहा है कि लोकसभा के अध्यक्षों ने यथा संभव निष्पक्षता से सदन की कार्रवाई का संचालन किया।

उल्लेखनीय है कि 15वीं लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने अपने ही दल के विरुद्ध निर्णय दिए थे जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। उन्हें दल से निष्कासित कर दिया गया। पर उन्होंने अपने पद की मर्यादा से समझौता नहीं किया। लेकिन पिछले 10 वर्षों से लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी लगातार विवादों में रहे हैं। उन पर सत्तापक्ष के प्रति अनुचित झुकाव रखने का आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। 17वीं लोकसभा में तो हद ही हो गई जब सत्तापक्ष के एक सांसद ने विपक्ष के सांसद को सदन की कार्रवाई के बीच बहुत ही अपमानजनक गालियां दीं। अध्यक्ष ने उनसे वैसा कड़ा व्यवहार नहीं किया जैसा वो लगातार विपक्ष के सांसदों के साथ करते आ रहे थे। तब तो और भी हद हो गई जब उन्होंने विपक्ष के 141 सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया। ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। हाल ही में एक टी.वी. चर्चा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत करते हुए देश के नामी वकील, सांसद और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि देश के संविधान के अनुच्छेद 105, संसद के सदस्यों को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। परंतु क्या सांसदों को ऐसा करने दिया जाता है? जबकि इसी अनुच्छेद में या पूरे संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी सांसद का, संसद सदन में, अपनी बारी पर बोलते समय, माइक बंद किया जा सकता है। यह भी कहीं नहीं लिखा है कि किसी सांसद को बोलते समय, यदि वह नियम व मर्यादा के अनुसार बोल रहा हो तो उसे टोका जा सकता। इतना ही नहीं यह बात भी नहीं लिखी है कि यदि विपक्ष किसी मुद्दे पर सत्तापक्ष का विरोध करे तो उसे टी.वी. पर नहीं दिखा सकते। परंतु आजकल ऐसा होता है और यदि लोकसभा अध्यक्ष इस बात को नकार देते हैं कि वे किसी का माइक बंद नहीं करते तो फिर कोई तो है जो माइक को बंद करता है। यदि ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है और किसके निर्देश पर कर रहा है? इसके साथ ही एक और भी अजीब घटना हुई, अब तक परंपरा यह थी कि लोकसभा का अध्यक्ष सत्तापक्ष से चुना जाता था और उपाध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता था। इससे सदन में संतुलन बना रहता था। पर पिछली लोकसभा में इस परंपरा को तोड़ दिया गया और बिना उपाध्यक्ष के ही पिछली लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया।

18वीं लोकसभा की शुरूआत ही ऐसी हुई है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी तक अनेक दलों के सांसदों ने लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये का खुला आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। ये न सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा के प्रतिकूल है, बल्कि ओम बिरला जी के निजी सम्मान को भी कम करता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि ओम बिरला जी मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना 'पंच परमेश्वर' को गंभीरता से पढ़ें जो शायद उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के दौरान पढ़ी होगी। इस कहानी यह शिक्षा मिलती है कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपने सगे-संबंधियों का भी लिहाज नहीं करना चाहिए। लोकसभा की सार्थकता और अपने पद की गरिमा के अनुरूप ओम बिरला जी को किसी सांसद को यह कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि उनका व्यवहार पक्षपातपूर्ण है।

एकात्मता के स्वर — लोक

भू: भुव: और स्व: अर्थात भूलोक, भुवर्लोक और स्वलोक। इन्हीं तीनों को त्रैलोक्य कहा गया है। भगवान् वामन ने विराट रूप धारण कर अपने पग से राजा बलि के दान देने पर नाप लिया था। व्यवस्था की दृष्टि से सात लोक ऊपर और सात नीचे कहे गये हैं।

पृथ्वी पर स्थित सभी स्थान जहाँ पैदल जाया जा सकता है वह भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भुवर्लोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्यलोक के बीच जो चौदह लाख योजन का अवकाश है उसे लोकस्थिति पर विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने स्वर्गलोक कहा है। ध्रुव से एक करोड़ योजन ऊपर महर्लोक बताया गया है। उससे भी दो करोड़ योजन तक फैला हुआ जनलोक है, जहाँ सनकादि निवास करते हैं। इससे भी ऊपर चार हजार करोड़ योजन तक तपलोक माना गया है, जहाँ वैराज नाम वाले देवता निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा छह गुने विस्तारवाला सत्यलोक विराजमान् है, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती है यानि ज्ञान प्राप्त करके वह ब्रह्मा जी के साथ युक्त हो जाते हैं। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उससे ऊपर अट्ठारह करोड़ पच्चीस लाख योजन पर परम कल्याणमय धाम प्रकाशित होता है, उसकी कोई उपमा नहीं है। वह सर्वोपरि विराजमान है। इनमें से जनलोक, तपलोक व सत्यलोक ये तीनों अकृतक (नित्य) लोक हैं। कृतक और अकृतक लोकों के मध्य में महर्लोक की स्थिति मानी गयी है। सात पाताल- भूमि की ऊँचाई सत्तर हजार योजन की है इसके भीतर सात पाताल हैं जो एक-दूसरे से दस-दस हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम-अतल, वितल, नितल रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल हैं। वहाँ की भूमियाँ सुंदर महलों से शोभित हैं। वे क्रमश: कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी हैं। उन पातालों में दानव, दैत्य और नाग संघ बनाकर निवास करते हैं। न वहाँ पर गर्मी है न सर्दी है न वर्षा न कोई कष्ट। ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग पाताल में हाटकेश्वर के नाम से है जिनकी सैकड़ों नाग आराधना करते हैं। उक्त तीनों लोकों को वामन से विराट बने भगवान् ने अपने तीन पगों से नापकर राजाबलि को सुतल लोक भेज दिया था।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अष्टादश-संख्या-विज्ञान (भाग-5)

गतांक से आगे...

साम को मुख्य या प्रथम मानने वालों की भावना यज्ञभयी नहीं है बल्कि वे सहृदय-हृदयैकवेहाता की भावना से गान को ही तत्काल श्रोतृ-मनो-मुग्धकारी समझते हैं यह प्रत्यक्ष भी अनुभव किया जा सकता है। अत: वे गीतिमन्त्रों को प्रथम स्थान देते है, इस भावना के अनुसार साम को प्रथम मानना स्वाभाविक ही है।

विज्ञानवाद में पृथ्वी-अन्तरिक्ष और द्यौ: इन तीनों स्थानों की देवतारूप परमात्मशक्तियों का वर्णन करना ही वेदों का मुख्य उद्देश्य है । उक्त स्थानों की प्रतिनिधि शक्तियें क्रमश: अग्नि वायु और आदित्य माने जाते हैं।

सो पृथ्वी-स्थानीय अग्नि देवता का निरूपक अग्निमीले शब्द से आरम्भ होने वाला पुग्नेद है और अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु देवता का प्रतिपादक इवे त्वोर्जेत्वा वायवस्थदेव: आदि शब्दों से आरम्भ होने वाला यजुर्वेद है। गथा द्यु:स्थानीय आदित्य देवता का प्रस्तादक सामवेद है। अत: वैज्ञानिक भावना में ऋक् यजु: साम यही क्रम युक्ति-संगत हो सकता है।

वेदों की भांति पुराणों के क्रम-विन्यास में भी भावना की विशिष्टता का ही साम्राज्य है। वेदव्यास जी ने जिन पुराणों में जो क्रम निर्दिष्ट किया है वह भी किसी भावना विशेष से प्रेरित हो कर ही किया है। हमने पुराणों के क्रमविन्यास का पार्थक्य मिलाने पर यह परिणाम निकाला है कि मुख्यतया तीन प्रकार का गणनाक्रम पुराणों में पाया जाता है। यदि हम इस पार्थक्य का तात्त्विक विश्लेषण करना चाहें तो उक्त तीनों क्रमों को इस प्रकार कह सकते हैं; पहिला सृष्टि-प्रक्रिया-प्रतिपादक विशिष्ट-क्रम - जो लिङ्ग, मार्कण्डेय, और श्रीमद्भाभवत पुराण में लिखा है और इस ग्रन्थ में भी अष्टादश-पुराण नाम शीर्षक के नीचे जिसे प्रधान स्थान दिया गया है।

क्रमश: ...

अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस

हिमाद्री सिंह

अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दोस्ती के बंधन को मजबूत करने और दुनिया भर में मित्रता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की शुरुआत पैराग्वे से हुई थी। साल 1958 में पैराग्वे में 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि 30 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने का उद्देश्य अलग-अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में योगदान देना है।

यह दिन विभिन्न संस्कृतियों और

पृष्ठभूमि के लोगों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का महत्व इसलिए भी है क्योंकि दोस्ती मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है। दोस्त हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, मुश्किल समय में सहारा देते हैं और प्रेरित करते हैं। दोस्ती एक-दूसरे को बेहतर समझने में मदद करती है और हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। दोस्तों का होना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दोस्त तनाव और डिप्रेशन से उबरने में मदद करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस दुनिया भर में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियां करते हैं, उपहार देते हैं, साथ में समय बिताते हैं और एक-दूसरे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। कुछ लोग इस दिन को समाज सेवा के लिए भी समर्पित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस दोस्ती का जश्न मनाने और हमारे दोस्तों को हमारे जीवन में उनके महत्व का एहसास कराने में मदद करने का एक अवसर है। यह दिन मनाने के कुछ तरीकों में अपने दोस्तों को उपहार देकर खुश करना, केक बनाना और शुभकामनायें संदेश लिखना जैसी चीजें शामिल है। एक सच्चा दोस्त हमें भावुक आवगमन, सुख-दुख में साथ देने, और एक-दूसरे के साथ समय बिताने का सामर्थ्य देते हैं। मित्र एक-दूसरे के साथ गहरे भावों के साथ जुड़े होते हैं, जो हमें सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते हैं। इस दिन को याद करना हमें यह बताता है कि मित्रता का महत्व और उसके प्रभाव को अभिवादन करना जरूरी है।

अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस विश्वभर के लोगों के बीच एकता और समझौते को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह एक दिन है जब हम अपने पुराने दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने और नए दोस्तों से मिलने का अवसर देखते हैं। मैत्री के भाव को समझने, समर्थन करने और देने का संकल्प करने के माध्यम से, हम विभिन्न समुदायों के बीच विश्वशांति और समृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं। संघर्षों और विभाजनों से भरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता और अन्य मतभेदों से परे है, लोगों के बीच करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देता है।

बांग्लादेश को कहां ले जाएगा ये छात्र आंदोलन

रहीस सिंह

'तुई के? अमी के? रजाकार, रजाकार! के बोलेचे, के बोलेचे, सैराचार-सैराचार।' यानी तुम कौन हो? मैं कौन हूं? रजाकार, रजाकार! कौन कहता, कौन कहता, तानाशाह, तानाशाह!' पिछले दिनों बांग्लादेश ने आंदोलनकारियों और सरकार के टकराव का जो एपिसोड लिखा उसमें ये आवाजें उठीं जो बहुत दूर तक गईं और बांग्लादेश भी गृहयुद्ध जैसी स्थिति में पहुंच गया। प्रश्न यह उठता है कि बांग्लादेश की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रोटेस्टर्स सड़क पर क्यों रहे? वे बांग्लादेश की जुडिशरी पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे?

कहने के लिए तो यह 1971 के मुक्ति युद्ध के मुक्ति योद्धाओं के लिए निर्धारित कोटा के खिलाफ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था लेकिन सही मायने में सरकार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई दिखी। ध्यान रहे, यह कोटा शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 1972 में मुक्ति योद्धाओं के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया था जिसकी सीमा 30 प्रतिशत थी। बाद में इसमें उनके पोते-पोतियों को भी शामिल कर लिया गया। बढ़ती बेरोजगारी के बीच युवाओं ने इसे अपने करियर के सामने एक बड़ी बाधा माना और विरोध शुरू कर दिया।

सरकार ने शुरू में इसे हल्के में लिया और समाधान खोजने के बजाय उनके साथ खेल खेलने लगी, जैसा कि सत्ताएं प्राय: करती हैं। आखिर यह खेल सरकार ने खेला कैसे? दरअसल 2018 में हाइकोर्ट में इस कोटा सिस्टम की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने 8 मार्च 2018 को सुनवाई करने के बाद इसे रिजेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स को यह नागवार गुजरा

क्योंकि वे इस कोटा सिस्टम में सुधार चाहते थे। नतीजतन, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सरकार ने एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर इस कोटा सिस्टम को रद्द कर दिया। 2020 में सरकार के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर को लागू भी कर दिया गया।

इसके बाद सरकार ने एक चोर दरवाजा खोला। वह था हाइ कमीशन, जिसने पुन: हाईकोर्ट में इस आशय की अपील फाइल की कि शेख हसीना सरकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही अवैधानिक है। परिणाम यह हुआ कि 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर को रद्द कर दिया और कोटा सिस्टम फिर से बहाल हो गया। स्टूडेंट्स ने सरकार से इस फैसले के खिलाफ एक्जीक्यूटिव ऑर्डर अथवा बिल लाने की अपील की। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी। स्टूडेंट समझ गए कि सरकार की मंशा सही नहीं है। फिर क्या था, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ढाका की सड़कें खून से सनी नजर आईं।

छात्र रिफॉर्म्ड कोटा सिस्टम चाहते हैं जिसमें 5 प्रतिशत महिलाओं और 1 प्रतिशत विकलांगों के लिए कोटा हो शेष नौकरियां मेरिट से मिलें। उनका मानना है कि बांग्लादेश में कुल आबादी के केवल 0.13 प्रतिशत को ही फ्रीडम फाइटर्स डिसेंडेंट का दर्जा हासिल है, फिर उनके लिए 30 प्रतिशत का कोटा क्यों। इसे भले अवैज्ञानिक कहा जा रहा हो, लेकिन यह कोटा सिस्टम अवामी लीग सरकार के लिए फायदेमंद बहुत था। यही वजह है कि शेख हसीना ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को पहले पॉलिटिकल टूल किट कहा, फिर रजाकार अथवा उनका समर्थक ताकि इन्हें कुचला जा सके। पुलिस के साथ-साथ स्पेशल फोर्सेज और आर्मी तैनात कर दी गई। पूरा देश कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लैक आउट से गुजरा।

बांग्लादेश के विषय में जो एक बात विचार करने वाली है, वह यह कि शेख हसीना के शासनकाल में उसने कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं। वर्तमान में बांग्लादेश रेडी-टू-वेयर कपड़ों के निर्यात का एक पावर हाउस है। यह क्षेत्र वैश्विक बाजार में लगभग 40 अरब डॉलर का निर्यात करता है और 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। पिछले 15 वर्षों में राजधानी ढाका में सड़कों, पुलों, कारखानों और मेट्रो रेल का जाल बिछ गया है। पिछले एक दशक में बांग्लादेश की प्रतिव्यक्ति आय तीन गुना हो गई है और विश्व बैंक के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में वहां 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

फिर भी मध्यम वर्ग सरकार के साथ नहीं दिखा, क्यों? इसका पहला कारण तो बेरोजगारी ही है जो 16 प्रतिशत से भी ऊपर है। यानी वहां हर 5वां व्यक्ति बेरोजगार है। यही वजह है कि युवा बेरोजगार कोटा सिस्टम के खिलाफ इस तरह आक्रामक हुआ। ऊपर से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ तानाशाही तरीका रवैया अपनाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के पोते-पोतियों को नहीं तो क्या 'रजाकार' के पोते-पोतियों को दें? इस तरह उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को रजाकारों का समर्थक बता कर उन्हें एंटी नेशनल का तमगा थमा दिया। यह प्रोटेस्टर्स को मंजूर नहीं था। दरअसल 'रजाकार' वे थे जिन्होंने 1971 के मुक्ति युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी की मदद की थी।

इस संदर्भ में एक सवाल शेख हसीना को इसी साल चुनावों में मिले जनादेश पर भी बनता है। अगर जनवरी में हुए चुनावों केवक्त देश के मतदाता शेख हसीना और उनकी पार्टी के साथ थे तो फिर अचानक उनके विरोध में इतना तगड़ा आंदोलन कैसे हो गया?ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक बांग्लादेश में 2024 के आम चुनाव न तो स्वतंत्र थे, न निष्पक्ष और न ही शांतिपूर्ण। निष्पक्ष कैसे होते जब 1500 से अधिक विपक्षी नेताओं को पहले ही अदालतों में दोषी बताते हुए प्रतिपक्ष को पंगु बना दिया गया था। यही वजह है कि प्रोटेस्टर्स को लगता है कि बांग्लादेश की न्यायपालिका एकपक्षीय है। वह वही कर रही है जो प्रधानमंत्री शेख हसीना चाहती हैं। यही वजह है कि वे कोटा सिस्टम पर जुडिशरी के फैसले के बाद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

आज का इतिहास

1932 अमेरिका के लास एंजिल्स में दसवें आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई।
1938 पहला बच्चों का कॉमिक द बीनो ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ।
1942 जर्मन की सेना ने बेलारूस के मिंस्क में 25000 यहूदियों की हत्या की।
1961 43 वीं पीजीए चैम्पियनशिप पूरी हो गई है। जेरी बार्बर ने ओलंपिया फील्ड्स ड्रुरुमें 277 की शूटिंग की। यह उनके द्वारा की गई एक शानदार उपलब्धि थी।
1966 आठवें फीफा विश्वकप में पश्चिम जर्मनी को हराकर इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप फुटबॉल जीता।
1972 बैरीमोर न्यूयॉर्क शहर में बंद नहीं किया गया था मरने के लिए माना जाता है। इसने 325 प्रदर्शन किए हैं। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी।
1974 वाटरगेट कवर-अप में राष्ट्रपति निक्सन को महाभियोग लगाने के लिए, हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने 3 और उच्च अपराधों और दुष्कर्मों के अंतिम आरोप पर वोट दिया।
1975 डेट्रोइट के पास एक रेस्तरां के बाहर आखिरी बार देखे जाने के बाद अमेरिकी मजदूर संघ के नेता जिमी होफा रहस्यमय तरीके से गायब हो गए।
1980 वनूआटो देश को स्वतंत्रता मिली।
1982 सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
2000 तीन बार लगातार फ्रांस का भ्रमण करने वाले लांस अर्मस्ट्रांग पहले अमेरिकी बनें।
2006 लेबनान युद्ध-इजरायली वायु सेना ने काना के दक्षिण लेबनानी गांव के पास तीन मंजिला हमला किया, जिसमें 16 बच्चों सहित कम से कम 28 सैनिक मारे गए।
2006 लेबनान युद्ध : इजरायली वायु सेना ने काना के दक्षिण लेबनानी गांव के पास तीन मंजिला हमला किया, जिसमें 16 बच्चों सहित कम से कम 28 नागरिकों की मौत हो गई।
2010 काबुल में दो अमेरिकी दूतावास की कारों में आग लगा दी जाती है।
2011 ज़ारा फिलिप्स, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की पोती ने माइक टिंडेल से शादी की। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड रग्बी यूनियन है।

मुलायम के लोहियावादी बोझ के बिना आधुनिक सोच रखते हैं अखिलेश

प्रभु चावला

एक समय की बात है, भारत में उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव नाम के एक महान पहलवान रहते थे। वे चक्र दाव में माहिर थे, यानी प्रतिद्वंद्वी को पटखनी देने की कला। उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश के विश्वासघाती राजनीतिक अखाड़े में बड़ी कुश्ती जीती और बाद में कई राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतियोगिताओं में रैफरी की भूमिका निभाई। उनके बेटे अखिलेश यादव ने स्टारडम का राज समझ लिया है। युवा सांसद अखिलेश अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए दोस्त बना रहे हैं और दुश्मनों को त्याग रहे हैं। अखिलेश सिर्फ एक सांसद नहीं हैं वे एक मुख्यमंत्री थे। जंतर-मंतर पर एन.डी.ए. के खिलाफ क्षेत्रीय दलों द्वारा आयोजित धरने पर बैठकर अखिलेश ने यह बात साबित कर दी कि क्षेत्रीय ही राष्ट्रीय है।

उन्हें आंध्र प्रदेश के अपदस्थ मुख्यमंत्री जगन मोहन रैड्डी ने आमंत्रित किया था, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि उनकी वाई.एस.आर. कांग्रेस के पास संसद में 15 सांसद हैं और एन.डी.ए. सरकार, जिसमें उनके प्रतिद्वंद्वी चंद्रबाबू नायडू भागीदार के रूप में शामिल हैं, को उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह और अखिलेश शायद ही कभी सामाजिक या राजनीतिक कारणों से मिले हों। फिर भी, यादव जूनियर ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। यह चतुराईपूर्ण दृष्टिकोण है। अखिलेश उत्तर भारत से आगे अपने राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और 2029 तक सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। एक युवा नेता अखिलेश जाति कार्ड नहीं खेलते हुए खुद को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं और मुलायम के लोहियावादी बोझ के बिना आधुनिक सोच रखते हैं। सपा के लिए, यादववाद मर चुका है। अखिलेश अब एक छोटे से यादववादी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं।

जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटों के साथ सपा को शानदार जीत दिलाई और 18वीं लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तब से वे अपनी पार्टी के अंदर और बाहर बहुत सक्रिय हैं। अब वे एक शांत स्वभाव वाले योद्धा नहीं रह गए हैं; वे व्यंग्य, कविता और शांत विचारधारा से भरपूर शोधपूर्ण भाषण देते हैं। वे विभिन्न दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और अपने घर या संसद के बाहर प्रतीक्षा कर रहे पत्रकारों को साक्षात्कार देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

राजनीतिक शैली में यह बड़ा बदलाव है। पिछले एक दशक से अखिलेश ने खुद को लखनऊ तक सीमित रखा और ज्यादातर करीबी लोगों से ही मिले, घर से सिर्फ पार्टी मीटिंग के लिए निकले। बाकी समय उन्होंने परिवार के साथ बिताया, घर के पिछवाड़े में फुटबॉल या क्रिकेट खेला। अब कई सालों के बाद भारत में एक नया युवा क्षेत्रीय राजा दिख रहा है जो राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए बेताब है। ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन और तेजस्वी यादव मोटे तौर पर अपने गृह राज्यों में ही रहे हैं, जबकि अखिलेश दिल्ली में अपने सांसदों से घुलमिल गए हैं। उन्होंने गठबंधन बनाने और तोडने की कोशिश की है। उन्होंने

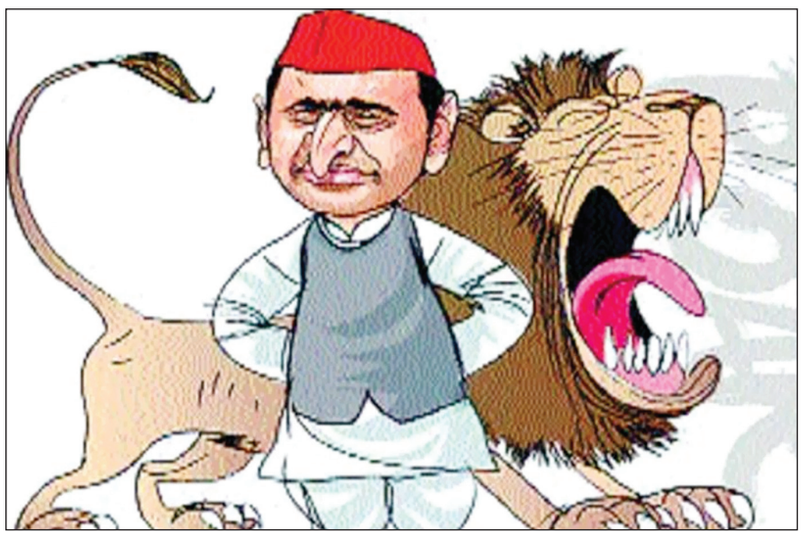

कांग्रेस और बसपा के साथ भी हाथ मिलाया, लेकिन असफल रहे। लेकिन वे लड़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उम्र उनके पक्ष में है। अखिलेश का लक्ष्य सपा को एक समावेशी मंच में बदलना और शीर्ष पर पहुंचाना है।

उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक शैली में बदलाव किया और दागी छवि वाले पुराने विश्वासघातियों को हटाकर अपना खुद का संस्करण गढ़ रहे हैं। मुलायम की जीत का टिकट उनका कांग्रेस विरोधी एजैंडा था। 2014 में, उन्होंने मतदान के दिन से ठीक पहले रातों-रात सपा के वोट कांग्रेस को हस्तांतरित करके अमेठी में राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित की। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वास मत हारने के बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भी वे ही जिम्मेदार थे। उन्होंने राष्ट्रपति को अपनी पार्टी के 39 सांसदों के समर्थन का पत्र देने से इंकार कर दिया। फिर भी, कुछ साल बाद, वे प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद के लिए उनका समर्थन मांगने के लिए 10 जनपथ गए।

अखिलेश आखिरकार अपने पिता की जगह लेने जा रहे हैं। हालांकि, दोनों में एक बड़ा अंतर है। उनकी पहली लड़ाई परिवार के सदस्यों के खिलाफ थी। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यू.पी. सपा प्रमुख नियुक्त किया था। अखिलेश की राज्यव्यापी रथ और साइकिल यात्राओं ने उन्हें यू.पी. का पहला युवा आइकन बना दिया, जिससे सपा को दो-तिहाई से अधिक सीटें मिलीं। जैसे ही अखिलेश ने खुद को सी.एम. के रूप में स्थापित करना शुरू किया, उन्हें परिवार के भीतर विद्रोह का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुलायम के पारिवारिक, राजनीतिक और नौकरशाही के उम्मीदवारों को बर्खास्त कर दिया। गुस्से में मुलायम ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बेटे ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पिता को अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद पार्टी की कमान संभाली। यह झगड़ा चुनाव आयोग तक गया, जिसने पार्टी और उसका चिन्ह अखिलेश को दे दिया। 2017 तक, अखिलेश पूरी तरह से प्रभारी थे।

अखिलेश के इर्द-गिर्द कोई यादव नहीं है। हालांकि यादवों ने 5 चुनाव जीते हैं। उन्होंने यादवों के नेतृत्व वाली पार्टी को यादवों से मुक्त कर दिया है। हालांकि पार्टी के आधे पद और विधायक सीटें यादवों ने हथिया लीं, लेकिन अखिलेश ने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि अगर उन्हें कभी भारत पर शासन करना है तो उन्हें अन्य समुदायों के साथ सत्ता सांझा करनी होगी। अखिलेश ने अपने पिता के मुस्लिम और यादव के राजनीतिक गठबंधन को कमजोर कर दिया और एक नया पी.डी.ए. (पिछड़े या पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक) नारा गढ़ा। पी.डी.ए. एक गेम-चेंजर था इसने 2024 में सपा को 5 सांसदों से 37 पर पहुंचा दिया। उम्मीदवारों की सूची में गैर-यादव बहुमत में थे। जैसा कि सी.एम. के रूप में उनके ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है, अखिलेश ने आधुनिकतावादी की भाषा बोलनी सीख ली है।

फिर भी, अखिलेश जल्दबाजी करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। 5 बार के लोकसभा सांसद, 38 साल की उम्र में सी.एम. और 45 साल की उम्र में पार्टी प्रमुख बने। वे सावधानी से अपना राजनीतिक रास्ता तय कर रहे हैं। वे अपनी राजनीतिक पहचान पर कायम हैं। हालांकि कांग्रेसियों ने गांधी टोपी छोड़ दी है, लेकिन अखिलेश लाल टोपी में हर राजनीतिक कार्यक्रम में अलग दिखते हैं। वे कोई कॉमरेड नहीं हैं, लेकिन दिल से समाजवादी हैं और उनका दिमाग उदार है। शांत और मृदुभाषी, अखिलेश ने योगी और मोदी सहित किसी भी भाजपा नेता के खिलाफ एक भी जहरीला शब्द नहीं बोला है। यू.पी. भले ही एक ध्रुवीकृत युद्ध का मैदान हो, लेकिन सी.एम. के रूप में योगी और विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश सभ्य राजनीतिक आचरण का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए राज्य पहले आता है। दोनों एक ही आयु वर्ग के हैं और लंबे समय में संभावित पी.एम. उम्मीदवार हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है कि दो 'यू.पी. के लड़कों' (राहुल और अखिलेश) में से कौन कप जीतेगा? 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आंशिक जवाब देंगे। मुलायम का सबक रहा है, 'अगर आप टूर्नामैंट जीतते हैं तो मैच हारना ठीक है'। इस मामले में, अखिलेश दोस्तों और दुश्मनों दोनों के खिलाफ खेल रहे हैं। राजनीति में कुछ स्थायी दुश्मन और दोस्त होते हैं, लेकिन स्थायी हितों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

विकसित भारत की दिशा में एक कदम

आर राजागोपालन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में अनेक ऐसी पहलें हैं, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि यह एक भविष्योन्मुखी बजट है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इन उद्यमों के लिए पूंजी उपलब्धता सुगम बनाने के लिए स्थापित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदारों के लिए टर्नओवर की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्यरत 50 खाद्य विकिरण इकाइयों को वित्तीय मदद देने की घोषणा भी की गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा तथा रोजगार के अवसरों के सृजन को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि बजट मध्य वर्ग, महिलाओं, गरीबों और ग्रामीणों को सशक्त बनायेगा। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने उसके चुनाव घोषणापत्र की कुछ योजनाओं को लिया है। इस बजट में भाजपा के मुख्य विचार हिंदुत्व की ध्वनि भी है। इसीलिए मंदिरों के लिए प्रावधान किये गये हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी आवंटन किया गया है। बजट के बाद समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने रेखांकित किया कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक बार भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश के विकास के बिना भारत का विकास संभव है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि बजट में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है तथा ग्रामीण विकास के संबंध में बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने शिकायत की कि कृषि क्षेत्र को सबसे कम आवंटन किया गया है तथा आप इंटर्नशिप भर देकर रोजगार नहीं दे सकते। विपक्ष जो भी कहे, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सामने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र को रखते हुए उसे बजट में लागू करने की कोशिश की है। कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने टिप्पणी की है कि दवाओं के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। आप चाहे जैसे बजट का विश्लेषण करें, पर निश्चित रूप से यह बजट शासन में स्थायित्व की आशा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है कि वे एक सुपरमैन हैं, जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं। इस बजट से यह संकेत भी मिलता है कि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा तथा जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को लाभ मिल सकता है। अब देखना है कि 27 जुलाई को नीति आयोग इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया देता है। संक्षेप में कहें, तो यह बजट विकसित भारत की दिशा में सही कदम है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि बजट घोषणाओं एवं प्रावधानों के सकारात्मक परिणाम जल्दी ही हमारे सामने आयेंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कमजोर कोई नहीं!

अमिताभ श्रीवास्तव

जैसे-जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का समय पास आ रहा है, वैसे-वैसे हर दल अपनी-अपनी तैयारी को शक्ल देता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में शानदार विजय मिलने के बाद राज्य की महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद हैं और उसमें शामिल हर दल की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। दूसरी ओर राज्य का सत्ताधारी महागठबंधन अपनी पराजय की भरपाई के लिए उतावला है। ऐसे में दोनों गठबंधन के सहयोगी अपनी-अपनी जगह ख्वाब सजाए हुए हैं। किंतु इस परिदृश्य में ऐसा लग रहा है कि राज्य की राजनीति में कोई कमजोर नहीं है। यहां तक कि अनेक दल अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी में हैं। इस कतार में आगे कांग्रेस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) जैसे दल हैं, जो अपनी ताकत से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं।

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होता है, जिनमें 29 पर अनुसूचित जाति, 25 पर अनुसूचित जनजाति और 234 पर सामान्य उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले सालों में कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी ने ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ा है, भले ही परिणाम कुछ भी सामने आए हो। इन दलों के अलावा किसी दल ने वर्ष 2014 को छोड़कर दो सौ पार जाने की हिम्मत नहीं जुटाई है। जिसकी वजह गठबंधन के लाभ के आधार पर चुनाव लड़ना है। किंतु इस बार आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले कई बार पूरी 288 सीटों पर ताल ठोंकने की बात कह चुके हैं, तो दूसरी ओर मनसे के प्रमुख ने गुरुवार को 225 से 250 तक सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्यक्ष रूप से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कार्यकर्ताओं को दस वोटों के फार्मूले से 200 सीटें जीतने का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं राज्य से सत्ताधारी गठबंधन में उसकी सहयोगी शिवसेना का शिंदे गुट 126 सीटों पर चुनाव लड़ने का इच्छुक है और 100 से कम सीटों पर समझौता करने की उसकी कोई योजना नहीं है।

जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा से

काम कर महागठबंधन पर दबाव बना रही है। यदि इस तैयारी से सत्ताधारी दलों की महत्वाकांक्षा को देखा जाए तो वह चुनाव के लिए उपलब्ध सीटों से बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसमें समझौते की गुंजाइश को देखा जाए तो पिछली बार भाजपा ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था।

जबकि उससे तालमेल कर शिवसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसलिए भाजपा के पास 124 सीटों पर ही समझौते का अवसर है। हालांकि वह 150 सीटों की बात कर 14 सीटें दूसरों को देने की इच्छुक है। इसी प्रकार एकजुट राकांपा ने पिछली बार 121 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से जीते विधायकों में 31 विधायक अजित पवार के गुट के पास माने जाते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा बढ़ना स्वाभाविक है।

वहीं, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा आगे आई है। हालांकि शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) का 115-120 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य है। राकांपा का शरद पवार गुट चाहता है कि गठबंधन के तीनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ें, जिसके अनुसार 96-96 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। किंतु कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोले की 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा बार-बार सहयोगियों की चिंता बढ़ा रही है। इनके बीच वंचित बहुजन आघाड़ी, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और मनसे के प्रत्याशी होंगे, जिनके दो सौ से अधिक होने का दावा किया जा रहा है। यदि राज्य के वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस को छोड़ शिवसेना तथा राकांपा का विभाजन हो गया है। इसकी बानगी लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। हालांकि राज्य के दोनों गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी मत विभाजन के चलते सफलता एक ही गठबंधन के खाते में आई। आगे भी तालमेल इसी तरह रहा तो विधानसभा चुनाव में स्थितियां अधिक नहीं बदलेंगी। फिर दावों की असलियत क्या बन पाएगी? पिछले विधानसभा चुनाव में मनसे ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 7.02 प्रतिशत मत हासिल किए थे। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी ने 236 सीटों पर मैदान में उतर कर 5.15 प्रतिशत मत प्राप्त किए थे। कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़कर 32.71 प्रतिशत मत पाए थे, जबकि उसकी सहयोगी राकांपा को 121 सीटों पर चुनाव लड़कर 38.13 प्रतिशत मत मिले थे। भाजपा को 44.51 प्रतिशत और शिवसेना को 38.13 प्रतिशत मत मिले थे। किंतु अब यह आधार नहीं है। मतों का बंटवारा अच्छी तरह से हो चुका है। यह माना जा सकता है कि चुनाव के पहले कोई भी दल अपने आप को कमजोर नहीं मान सकता है और पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोंक सकता है। मगर वास्तविकता तो चुनाव परिणामों के आधार पर लिखी जाएगी। राज्य में यदि कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा बार-बार दिखा रही है तो उसने वर्ष 1995 में 286 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब उसे 80 सीटों पर विजय मिली थी। उसके बाद उसे वर्ष 2014 में 287 सीटों पर चुनाव लड़कर 42 सीटों पर सफलता मिली। इसी साल राकांपा ने पहली बार स्वतंत्र चुनाव से 278 सीटों पर लड़ा, लेकिन 41 सीटों पर ही विजय मिली। इसी साल भाजपा ने 260 और शिवसेना ने 282 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें भाजपा को 122 तथा शिवसेना को 63 सीटों पर सफलता मिली। इन सभी चुनाव में अलग लड़ने का लाभ केवल एक बार भाजपा को मिला, जो उसे वर्ष 2019 में गठबंधन करने के बावजूद दोहराते नहीं बना। स्पष्ट है कि मिश्रित राजनीति के परिदृश्य में महत्वाकांक्षा का तब तक कोई महत्व नहीं है, जब तक कि उसका कोई ठोस आधार तैयार नहीं हो। इन दिनों संगठन की स्थिति, वैचारिक मतभेद और जातिगत आंदोलन किसी भी दल के लिए पोषक वातावरण तैयार नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे में चुनाव के पहले गीदड़ भभकी भले ही कोई दे, लेकिन पिछले 29 साल में कोई भी दल बिना गठबंधन के सरकार बना नहीं सका है। इसलिए माहौल बनाने के लिए चाहे कितनी भी तैयारी की जाए, सफलता गठबंधन में ही छिपी है।

मोदी 3.0 में खुलकर जिएगा स्वयंसेवक

अभिनय आकाश

नजरें जितनी नजदीक तक जाती हैं उतनी ही तरेरती भी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर हमेशा से विरोधियों के द्वारा सवाल उठाए जाते रहे हैं। ये कांग्रेस और पूरे विपक्ष के लिए फेक नैरेटिव सेट करने वाला फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। संघ पर बोलने का कोई मौका मिल जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक ही भाषा में बोलने लग जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और आरएसएस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में आपने ये दावे कई लोगों के मुंह से सुने होंगे की सहयोगियों के सहारे सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हो गए हैं। मोहन भागवत ने लोककल्याण मार्ग पर मिसाइल चला दी है। लेकिन इन दोनों एजेंडों को मोदी के आरएसएस कार्ड से सीधा जवाब मिला है। आरएसएस को लेकर पहले ऐसे किसी फैसले में नरेंद्र मोदी सरकार ने 58 साल से सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर लगा बैन हटा दिया है। इस पर हंगामा मचना तय था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहा जाने लगा कि मोदी विचारधारा के आधार पर सरकारी दफ्तरों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कर्मचारियों की निष्पक्षता और संविधान की सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। कहा जाने लगा कि संविधान बदलने का इरादा कामयाब नहीं हुआ तो संस्थानों पर कब्जे की तैयारी हो रही है। ऐसे में चर्चा ये है कि नरेंद्र मोदी का आरएसएस कार्ड किसको संदेश दे रहा है। क्या मोहन भागवत के दबाव में आने के विपक्ष के दावे में दम है या फिर ये राहुल गांधी को मोदी का जवाब है। 58 साल पहले ये बैन लगा क्यों और मोदी सरकार ने इसे अब क्यों हटाया? सारे सवालों का एमआरआई स्कैन करेंगे।

आपको सबसे पहले 58 साल पहले के उस आदेश के बारे में बताते हैं जिसके जरिए इंदिरा गांधी की सरकार ने

आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगाया था। नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस वाला ये बैन लगाया था उसके पहले 7 नवंबर को गौ हत्या वध पर कानून बनाने की मांग को लेकर आरएसएस समर्थित आंदोलन को पुलिस की गोलियों से कुचला गया था। कई साधु संत इस गोलीबारी में मारे गए थे। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के अनुसार जनसंघ आरएसएस के प्रभाव से हिल गई। इंदिरा गाधी ने सरकारी कर्माचरियों पर आरएसएस में शामिल होने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रम में जाने पर बैन लगा दिया। दलील ये दी गई कि आरएसएस राजनीतिक रूप से प्रभावित है। आरएसएस की तरफ से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है।

30 नवंबर, 1966 को गृह मंत्रालय (डीओपीटी 1998 तक इसका हिस्सा था) ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकारी कर्मचारियों द्वारा जमात-ए-इस्लामी की सदस्यता या गतिविधियों में किसी भी भागीदारी के संबंध में सरकार की नीति के बारे में कुछ संदेह उठाए गए हैं। सरकार ने हमेशा इन दोनों संगठनों की गतिविधियों को ऐसी प्रकृति का माना है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनमें भाग लेने पर केंद्र के नियम 5 के उप-नियम (1) के सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 प्रावधान लागू होंगे। परिपत्र में कहा गया कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो उपरोक्त संगठनों या उनकी गतिविधियों का सदस्य है या अन्यथा जुड़ा हुआ है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। 1964 के नियमों का नियम 5 राजनीति और चुनावों में भाग लेने के बारे में है। नियम 5(1) कहता है- कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी संगठन का सदस्य नहीं होगा। अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968, जो आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर लागू होते हैं। केंद्र सरकार के मानव संसाधनों का प्रबंधन करने वाली डीओपीटी ने 9 जुलाई के आदेश में कहा गया है कि निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह फैसला लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र हटा दिया जाए। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं।

ये तीनों सर्कुलर तब जारी किए गए थे जब इंदिरा पीएम थीं। हालाँकि, सभी सरकारों का आरएसएस के प्रति एक ही दृष्टिकोण रहा है। 1980 और 90 के दशक में जब राजीव गांधी, पी वी नरसिम्हा राव और राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा सरकारें सत्ता में थीं, 1966, 1970 और 1980 के परिपत्र लागू रहे। यह स्थिति तब नहीं बदली जब अटल बिहारी वाजपेयी, जो स्वयं एक स्वयंसेवक थे, 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री थे। यही नीति 2014 से 9 जुलाई तक नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्षों तक जारी रही। आरएसएस, जो खुद को एक गैर-राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठन बताता है, ने बार-बार कहा है कि उसकी गतिविधियाँ ऐसे प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होती हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले एक सांसद ने कहा कि पहले भी सरकारी कर्मचारी संघ की गतिविधियों में भाग ले रहे थे।

एक-दूसरे की संस्कृति को दें सम्मान

डॉ संजीव

कर्नाटक के एक किसान के कारण धोती चर्चा में है। इस विवाद के कारण एक मॉल को सरकार ने एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया। बेंगलुरु के उस मॉल में धोती पहने एक किसान फकीरप्पा को फिल्म हॉल में जाने से रोक दिया गया था। लोगों के प्रतिरोध और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपने बेटे के साथ फिल्म देखने की इजाजत मिली। आजादी के आंदोलन को देखें, तो गांधी जी से लेकर राजेंद्र प्रसाद तक तमाम नेता धोती पहने दीखते हैं। हमारे अनेक प्रधानमंत्री और कई वरिष्ठ नेता प्राय: धोती पहनते रहे हैं। वैसे अब राजनीति में भी नियमित धोती पहनने वाले कम हो चले हैं। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, धोती प्रचलन से बाहर हो रहा है। दरअसल, जब हम किसी दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो हम भाषा के साथ कुछ व्यवहार भी अपनाते हैं। कई बार हम अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व के नाते कुछ विशेष कौशलों को अधिक महत्व देते हैं। 'सनलाइट ऑन द गार्डन' किताब में प्रो आंद्रे बेते ने अपने बचपन की एक घटना बतायी है। उनकी माता एक परंपरागत बंगाली महिला थीं, तो सभी बच्चे हाथ से खाना खाते थे। उनके एंग्लो-इंडियन पिता के एक दोस्त लंदन से आये, तो उनको घर पर खाने के लिए बुलाया गया। सभी को हाथ से खाता देख अथिति ने चम्मच छोड़ कर हाथ से खाने की कोशिश की। लेकिन उनके हाथ से चावल नीचे गिर जाता था। कई वर्ष बाद प्रो आंद्रे बेते को यह बात समझ में आयी कि यदि चम्मच से खाना एक कौशल है, तो हाथ से खाना भी एक कौशल है। इसमें कोई व्यवहारहीन या महान नहीं है। लेकिन जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, तो उसके संस्कार भी धीरे-धीरे हमारे व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। विशेष रूप से जहां अंग्रेजी का प्रभुत्व दिखता है, वहां अंग्रेजी संस्कृति भी अपनी छाप छोड़ने लगती है। हाथ के बजाय चम्मच से खाना भाषा का व्यवहार पर असर का एक संकेत है। भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता के संदर्भ में नुंगी वा थयोगो की बात को अगर इस संदर्भ में रख कर देखें, तो दूसरी भाषा और संस्कृति की उपलब्धियों को जानने-अपनाने से पहले अपने, इतिहास, कला, साहित्य, थियेटर, नृत्य की शिक्षा जरूरी है। पर अंग्रेजी के वर्चस्व से मातृभाषा में शिक्षा का सवाल धुंध में ढंक जाता है। हम अपने गांव-घर में भोजपुरी बोलते थे, स्कूल में हिंदी माध्यम था और फिर 'प्रोफेशनल' जरूरत से अंग्रेजी में काम करने लगे। लेकिन शहर में आ जाने से अगली पीढ़ी के सामने भोजपुरी की कोई उपयोगिता और परिवेश नहीं रहा। अंग्रेजी स्कूल का असर यह भी रहा कि पुरानी पीढ़ी के धोती-लुंगी अब ट्रैकसूट और शॉर्ट्स, टी-शर्ट्स में बदल गये। भाषा का असर खान-पान पर भी रहा। कटहल-परवल की जगह अब पनीर और मशरूम ने ले लिया। धोती और पैंट अब दो अलग-अलग आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान के वस्त्र बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी धोती पहनने वाले लोग अब कम हो रहे हैं। महिलाओं के पहनावे में भी बदलाव आया है। जिन इलाकों में महिलाओं में साड़ी का चलन था, वहां भी सलवार-कुर्ता आम हो गया है और उसके दुपट्टा अनिवार्य नहीं रह गया हैं। साल 1980 के बाद से टीवी-फिल्मों का असर पुरुष-महिला सभी के परिधान पर देखा जा सकता है। सफारी सूट, चौड़ी मोहरी के पैंट, जींस, चुस्त पैंट, सभी फिल्मों के कारण चलन में आये। सभ्यता के प्रारंभ में कुछ वर्षों तक निर्वस्त्र रहने के बाद मनुष्य ने पत्तों और जानवरों की खाल पहनना आरंभ किया। सभ्यता के विकास के साथ वस्त्र बदलते रहे।

कामिका एकादशी के दिन करें ये उपाय, हर कामना होगी पूरी

पंचांग के अनुसार, साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी जो इस बार 31 जुलाई, दिन बुधवार की पड़ रही है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।

हिन्दू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार, साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी जो इस बार 31 जुलाई, दिन बुधवार की पड़ रही है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं, ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि इस एकादशी के अवसर पर कुछ ज्योतिष उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आप अनेकों लाभ पा सकते हैं। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से आइये जानते हैं कामिका एकादशी के उपायों के बारे में विस्तार से।

धन लाभ के उपाय

कामिका एकादशी के दिन 5 कौड़ियां लें और उन कौड़ियों को लाला कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। फिर इसके बाद कौड़ियों को घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन लाभ के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कामना पूर्ति के उपाय

भगवान विष्णु के बीज मंत्र ऊँ नमो: नारायणाय नम: का 108 बार संकल्प के साथ कामिका एकादशी के दिन जाप करें। संकल्प के साथ इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा होगी और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपके काम बनने लग जाएंगे।

वैवाहिक जीवन के उपाय

गुलाब या कमल के 2 फूल लेकर उन्हें कलावे से बांधें और उसमें 7 गांठ लगाएं। फिर उस गुलाब या कमल के जोड़े को भगवान विष्णु के चरणों में रखें। इससे आपके वैवाहिक जीवन का क्लेश दूर होगा। पति-पत्नी के बीच रिश्ता मधुर बनेगा और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे।

ग्रह दोष मुक्ति के उपाय

कामिका एकादशी के दिन पीले रेशमी कपड़े में 9 सुपारी रखें और उन सुपारियों पर अक्षत एवं रोली लगाएं। इसके बाद गांठ बांधकर घर की पूर्व दिशा में टांग दें। इससे ग्रह दोष दूर होगा। ग्रह शांत होकर कृपा बरसाएंगे और ग्रहों द्वारा आपको शुभ परिणाम नजर आएंगे।

सावन की पहली एकादशी कामिका एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती है।

पंचांग के हिसाब से हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन कामिका एकादशी मनाने की परंपरा है। यह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। अब ऐसे में सावन की पहली एकादशी यानी कि कामिका एकादशी कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी तिथि का महत्व क्या है। इसके बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं।

कामिका एकादशी कब है

हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को संध्याकाल 04 बजकर 44 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 31 जुलाई को संध्याकाल 03 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी। बता दें, हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार के लिए सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। इसलिए तिथि के हिसाब से 31 जुलाई को सावन माह की पहली एकादशी मनाई जाएगी।

पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

शास्त्र के हिसाब से भगवान विष्णु की पूजा प्रात- काल में करने की मान्यता है। इसलिए साधक 31 जुलाई को सुबह 05.32 से सुबह 07.23 मिनट के बीच भगवान विष्णु की पूजा-पाठ विधिवत रूप से कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है।

कामिका एकादशी के बन रहे हैं शुभ योग

कामिका एकादशी के दिन ध्रुव योग बन रहा है। यह योग दोपहर 02 बजकर 14 मिनट तक है। ज्योतिष शास्त्र में ध्रुव योग को बेहद शुभ माना जाता है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधकों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर है।

कामिका एकादशी का महत्व क्या है?

कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है। उसे सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। इस व्रत को करने से जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दे, सावन के महीने में यह एकादशी व्रत पड़ता है। जिसका कारण इस एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ भगवान

शिव का आराधना करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं।

कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को लगाएं ये भोग, घर में बनी रहेगी बरकत

हिन्दू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार, साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी जो इस बार 31 जुलाई, दिन बुधवार को पड़ रही है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि सावन में आने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव ही इस एकादशी का फल प्रदान करते हैं। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि सावन की कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की जो भी पूजा हम करते हैं वो भगवान शिव के भाग में जाती है, उसे भगवान शिव स्वीकार करते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान विष्णु को लगाया भोग भी शिव जी द्वारा सी ग्रहण किया जाता है। ऐसे में आइये जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कौन सी चीजों का भोग लगाना चाहिए और क्या है उससे मिलने वाले अद्भुत लाभ।

कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। बेसन या बूंदी से बने लड्डू भगवान विष्णु को प्रिय हैं। इसके अलावा, भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। हालांकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित माना गया है। ऐसे में मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो मखानों को भून कर भी भोग में भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को कामिका एकादशी के दिन मालपुए या घेवर का भोग भी लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई नया मौसम शुरु होता है तो उस मौसम के फल या मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अभी घेवर का समय चल रहा है। ऐसे में आप कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को घेवर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही, मालपुए का भोग भी भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। मालपुआ श्री हरि को प्रिय है।

सावन में कांवड़ का है विशेष महत्व, कितने तरह की होती है ये यात्रा

सावन मास के प्रारंभ होने के साथ-साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िया गंगा नदी में स्नान कर लौटे में जल भरकर से शिव मंदिर में सावन शिवरात्रि के दिन अभिषेक करते हैं। कांवड़िया भगवान शिव से प्रार्थना कर आशीर्वाद मांगते हैं, इस कांवड़ यात्रा को लेकर यह मान्यता है कि भगवान शिव कांवड़िया की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं।

कितने प्रकार की होती है कांवड़ यात्रा

सामान्य कांवड़ यात्रा

सामान्य कांवड़ यात्रा में शिव भक्त चलते-चलते जब थक जाते हैं तो बीच-बीच में आराम कर सकते हैं। आराम के दौरान कांवड़ियों को इस बात का खास ध्यान देना पड़ता है कि कांवड़ बीच में जमीन पर न रखें। कांवड़िया अपने साथ स्टैंड लेकर चलते हैं, साथ ही वे कांवड़ को किसी पेड़ की डाल पर भी टांग देते हैं।

डाक कांवड़ यात्रा

डाक कांवड़ यात्रा में कांवड़िया विश्राम नहीं करता है। जब वह पवित्र नदी से स्नान कर जल भरता है तब वह सीधा मंदिर में जाकर रुकता है। डाक कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़िया बीच में किसी भी चीज के लिए नहीं रुकते और उनकी यात्रा को सरल बनाने के लिए मार्ग में कई तरह की उचित व्यवस्था की जाती है।

खड़ी कांवड़ यात्रा

खड़ी कांवड़ यात्रा में साधक कांवड़ लेकर चलते हैं। इस खड़ी कांवड़ यात्रा में 2-3 लोग साथ में चलते हैं, जिसमें एक के थकने पर दूसरे लोग कांवड़ लेकर साधक की यात्रा पूरी करने में सहायता करते हैं।

दांडी कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा के सभी प्रकारों में दांडी कांवड़ यात्रा सबसे कठिन मानी गई है। इस दांडी कांवड़ यात्रा में कांवड़िया पवित्र नदी से स्नान कर जल भरता है और मंदिर तक दंडवती करते हुए पहुंचता है। इस यात्रा में सबसे ज्यादा समय लगता है।

कौन सी कांवड़ यात्रा है सबसे सरल और सबसे कठिन

सबसे सरल की बात करें तो सामान्य कांवड़ यात्रा सबसे सरल है। इस यात्रा में कांवड़िया बीच-बीच में कांवड़ को स्टैंड पर रखकर आराम कर सकता है। वहीं दांडी कांवड़िया कांवड़ यात्रा के सभी प्रकार में सबसे ज्यादा कठिन है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िया दंडवती करते हुए भगवान शिव को कांवड़ का जल अर्पित करता है।

यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन में क्यों नहीं रखना चाहिए?

सावन मास में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है, इस माह में कांवड़िया कांवड़ में जल भरकर शिव जी का अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कांवड़ को जमीन पर क्यों नहीं रखते? कांवड़ को जमीन में नहीं रखने के पीछे एक धार्मिक मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार कांवड़ियों का मानना है कि कांवड़ भगवान शिव का स्वरूप है, जिसे कभी भी जमीन में रखकर उसका अपमान नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा कांवड़ में भरा हुआ जल भगवान शिव को चढ़ता है, ऐसे में कांवड़िया जमीन पर रखे हुए जल को भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। जिस मार्ग में कांवड़िया विश्राम के लिए रुकते हैं, उस स्थान में कावड़िया स्टैंड या पेड़ पर कांवड़ को रखते हैं, ताकि कांवड़ जमीन को स्पर्श न हो।

सावन में रुद्राभिषेक के लिए पांच दिन हैं उत्तम... राहु, केतु और शनि भी हो जाएंगे शांत

भगवान शंकर के प्रिय माह सावन में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से कई विपदाओं से मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी रुद्राभिषेक का वर्णन किया गया है। रुद्राभिषेक करने से घर में शांति बनी रहती है और ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। यह माह 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलने वाला है। इस पूरे महीने शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इस माह भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान होता है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। कांवड़ यात्री पवित्र नदियों से जल भरकर अपने कांवड़ में लाते हैं और अपने आसपास के शिवालयों में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं।

रुद्राभिषेक करने की सही तिथि

सावन में रुद्राभिषेक का खास महत्व होता है। लेकिन किस दिन रुद्राभिषेक किया जाना चाहिए, इसे लेकर कन्फ्यूजन बना रहता है। आइए, जानते हैं कि सावन में रुद्राभिषेक के लिए उत्तम दिन कौन-सा है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का अभिषेक तो किया ही जाता है, लेकिन रुद्राभिषेक करने के खास महत्व होता है। कहा जाता है कि इससे जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस बार सावन के महीने में ऐसी कई शुभ तिथियां आने वाली हैं, जिस दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है।

सावन में इस दिन करें रुद्राभिषेक

सावन शिवरात्रि का दिन भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए काफी खास माना जाता है। इस दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन शिव जी की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। इस साल 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि पड़ रही है।सावन माह की शिवरात्रि और सोमवार के साथ-साथ नागपंचमी पर भी रुद्राभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन रुद्राभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है।

इस साल सावन मास में नागपंचमी पर्व 9 अगस्त 2024 को मनाया जाने वाला है।

सावन सोमवार का दिन भी रुद्राभिषेक के लिए उत्तम होता है। इस बार सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त और पांचवां सोमवार 19 अगस्त को पड़ रहा है।

शास्त्रों में मिलता है रुद्राभिषेक का वर्णन

इन सभी तिथियों पर शिवजी का रुद्राभिषेक करने से जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही कोई बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे परिवार पर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि रुद्राभिषेक करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, इससे सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यदि आप सावन शिवरात्रि, सावन सोमवार या सावन प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक विधि-विधान से करेंगे, तो आपको चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। शास्त्रों में रुद्राभिषेक को शिव जी को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय बताया गया है भगवान शंकर के प्रिय माह सावन में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से कई विपदाओं से मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी रुद्राभिषेक का वर्णन किया गया है। रुद्राभिषेक करने से घर में शांति बनी रहती है और ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सीबीआई ने केजरीवाल खिलाफ दायर किया आरोपपत्र

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने

उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में आरोपपत्र दायर किया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी थी। इस मामले में आठ अगस्त को सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई थी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुईं थीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के. कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

इजराइल पर इतना क्यों भड़क रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा?

नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी

वाड्रा ने एक बार फिर गाजा में इजराइल के घातक और विनाशकारी हमले के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। उन्होंने उस युद्ध को बर्बर बताया है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और हर देश से इजराइल सरकार की नरसंहारक कार्रवाइयों की निंदा करने को कहा है। उनकी टिप्पणी तब आई जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले अक्टूबर में इजरायल-हमास युद्ध की शुरुआत के बाद अमेरिकी कांग्रेस को अपने पहले संबोधन में कहा था कि वह हमास के खिलाफ संपूर्ण जीत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने युद्ध को बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष के रूप में भी परिभाषित किया। प्रियंका इजरायल पर इन दिनों खासा हमलावर हैं। दरअसल, दावा किया जा रहा है कि वायनाड में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं।

प्रशांत किशोर ने बढ़ाईं नीतीश-लालू की मुश्किलें

पटना। राजनीतिक रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज को 2 अक्टूबर, गांधी जयंती पर एक राजनीतिक पार्टी का नाम दिया जाएगा। बिहार में एक अभियान के रूप में शुरू हुआ जन सुराज इस साल एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी जन सुराज की योजना की घोषणा की थी। प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, किशोर ने जन सुराज बैनर के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) श्रेणी से कम से कम 75 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का अपना इरादा भी बताया था। प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित प्रमुख राजनेताओं के लिए चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। किशोर ने पुष्टि की है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे।

सपा ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की

अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन करने में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में एक बैठक के बाद सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र से सातवीं बार विधायक चुने गए माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में, खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए (पिछडे, दलित, अल्पसंख्यकों) को गुमराह किया और उनका वोट ले लिया, लेकिन उप्र विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इन समुदायों की उपेक्षा की गई, यह भी सोचने की बात है।

मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से

योगी आदित्यनाथ को हटाने का अभियान चलाने वालों के हाथ एक बार फिर निराशा लगी है क्योंकि भाजपा आलाकमान ने तय किया है कि प्रदेश सरकार के नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यह भी बताया जा रहा है कि दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी अपने पदों पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने आज लखनऊ में भाजपा विधायक दल की बैठक में भाग लिया और इस दौरान तीनों आपस में बातचीत करते और मुस्कुराते हुए भी नजर आये। हम आपको बता दें कि हाल तक ऐसी खबरें थीं कि केशव प्रसाद कैबिनेट की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक भी मुख्यमंत्री से नाराज बताये जा रहे थे। खुद मुख्यमंत्री भी कई बैठकों में अपने दोनों उपमुख्यमंत्रियों को नहीं बुला रहे थे जिससे टकराव की खबरों को बल मिल रहा था। केशव प्रसाद ने तो सरकार से बड़ा संगठन है, की बात कह कर संकेत दिये थे कि वह सरकार से संगठन में जाना चाह रहे हैं।

राहुल गांधी बजट बनाने की प्रक्रिया में ढूंढ लिया जाति-धर्म

■ **लोकसभा में राहुल गांधी ने किया टैक्स टैररिज्म का जिक्र**

नईदिल्ली। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया। बजट में अग्निवीरों को पेंशन के लिए रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता ने आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी इतना बड़ा काम नहीं है। अगर बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाता तो किसान चक्रव्यूह से निकल जाता। 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे।

20 अफसरों ने मिलकर हिंदुस्तान का बजट बनाया है, जिसमें सिर्फ एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी है। बजट का हलवा बंट रहा है, लेकिन इसमें देश के 73% लोग हैं ही नहीं। मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से देश के किसानों से कहना चाहता हूं-हम किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। देश का मध्यम वर्ग शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। क्योंकि जब कोरोना में प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग से थाली बजाने और मोबाइल की लाइट जलाने के लिए कहा, तो उन्होंने ये सब किया। लेकिन इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडेक्शन और कैपिटल गेन टेक्स बढ़ाकर मध्यम वर्ग के लोगों पर ही प्रहार किया है।

वित्त मंत्री जी ने बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की। एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम देश की 500 बड़ी कंपनियों में होगा। 99% युवाओं का इस प्रोग्राम से कोई लेना-देना नहीं है.. यानि आपने पहले टांग तोड़ दी, फिर आप बैंडेज लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपने बेरोजगारी और पेपर लीक का चक्रव्यूह बना दिया है। युवाओं के लिए पेपरलीक आज सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बजट में इसकी बात नहीं की गई। इसके उलट आपने शिक्षा का बजट घटा दिया है।

आप चाहते हैं तो मैं अंबानी-अडानी का नाम लिस्ट से निकाल देता हूं

राहुल गांधी ने बजट भाषण पर बोलते हुए कहा कि अपने पिछले भाषण में मैंने कुछ धार्मिक अवधारणाओं के

बारे में बात की थी। शिव जी की अहिंसा की अवधारणा, तथ्य यह है कि त्रिशूल उनकी पीठ के पीछे रखा जाता है और हाथ में नहीं रखा जाता है। मैंने शिव जी के गले में सांप के बारे में बात की, और मैंने यह भी कहा कि कैसे हमारे देश में सभी धर्म अहिंसा के विचार का प्रस्ताव करते हैं और इसे डरो मत, डरो मत वाक्यांश में समाहित किया जा सकता है।

राहुल ने कहा कि मैंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत से परे एक विचार है, अभय मुद्रा का विचार, जो हर किसी के प्रति स्नेह और अहिंसा की भावना को स्थानांतरित करता है। भारत में डर का माहौल है और यह डर हमारे देश के हर हिस्से में व्याप्त है। समस्या यह है कि भाजपा में केवल एक ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने की अनुमति है। अगर रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो यह एक बड़ी समस्या है; डर है। यह डर पूरे देश में फैला हुआ है, और मैं खुद से यह सवाल पूछता हूं कि यह डर इतनी गहराई तक क्यों फैल रहा है? ऐसा क्यों है कि भाजपा में मेरे मित्र भयभीत हैं, मंत्री भयभीत हैं, किसान भयभीत हैं, कार्यकर्ता भयभीत हैं?

राहुल गांधी ने एक बार फिर अंबानी-अडानी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ए1 और ए2 की रक्षा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ए1 और ए2 की रक्षा करना चाहते हैं, हम समझते हैं। दरअसल, राहुल गांधी ने यह बात स्पीकर ओम बिरला द्वारा उनके नाम का इस्तेमाल करने से रोकने के बाद कही। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि आज देश को छह लोग कंट्रोल करते हैं। ये छह लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अंबानी और अडानी हैं। केंद्रीय बजट पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में हंगामा हो गया। राहुल के इस बयान पर स्पीकर ने टोकते हुए कहा कि आप संविधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लेना है। आपने लिख कर दिया है। ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा करता हूं कि वो नियमों का पालन करेंगे। राहुल ने इसके जवाब में कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं एनएसए और अंबानी-अडानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। किरण रिजिजू ने गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, आप सदन के नियमों को नहीं जानते, आप सदन के अध्यक्ष को चुनौती देते हैं।

अभिमन्यु की तरह हिंदुस्तान के लोगों को फंसाया गया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस सरकार में देश में डर का माहौल है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भी डरे हुए हैं। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को छह लोगों ने चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था। चक्रव्यूह के अदंर डर, हिंसा होती है। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है। पद्मव्यूह मतलब लोट्स फॉरमेशन। चक्रव्यूह जो होता है वो लोट्स यानी कमल के आकार में होता है। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। वो भी लोट्स के आकार का है। उसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो अभिमन्यु के साथ किया गया था। उसे फंसाया गया था वहीं हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, हामारी माताओं-बहनों, छोटे व्यापारियों के साथ किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वथामा, कृतवर्मा और शकुनी हैं। आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं। राहुल ने कहा कि वैसे तो चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं। लेकिन बिल्कुल सेंटर में छह लोग उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे। आज भी छह लोग कंट्रोल करते हैं। ये छह लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अंबानी और अडानी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट की नीयत केवल एकाधिकार वाले उद्योगपतियों, एकाधिकार वाली राजनीति और एजेंसियों को मजबूत करने की है। देश में 'कर आतंकवाद' है, इसे रोकने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है।

संसद में गूंजा कोचिंग हादसे का मामला

नईदिल्ली। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने आप सरकार की आलोचना करते हुए इस त्रासदी के लिए उनकी पूर्ण उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया और गृह मंत्रालय से जांच की मांग की।

स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, आम आदमी पार्टी की आपराधिक लापरवाही के कारण इन छात्रों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार पर जांच बैठाई जानी चाहिए । दिल्ली में नालों की सफाई क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने संसद में शून्यकाल के दौरान ये चिंताएं उठाईं।

अधिकारियों ने बताया कि जल निकासी व्यवस्था और सुरक्षा उपायों की कमी के साथ-साथ बेसमेंट के अवैध व्यावसायिक उपयोग ने मौतों में योगदान दिया। उचित बुनियादी ढांचे की कमी और मानदंडों का पालन न होना इस दुखद घटना में महत्वपूर्ण कारक थे।तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सुरक्षा संहिता के उल्लंघन को उजागर किया और पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नालों की सफ़ाई की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए। थरूर ने मामले की गहन जांच की भी मांग की।

समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस घटना को दुखद बताया और जिम्मेदारी तय करने के लिए विस्तृत जांच की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से अवैध इमारतों को गिराने जैसी

कार्रवाई यहां भी की जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने रविवार को राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इस घटना से संबंधित अन्य अपराधों के अलावा गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोचिंग सेंटरों के लिए जारी की गाइडलाइंस

नईदिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा को

बताया कि सरकार ने इस साल जनवरी में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। यह घोषणा दिल्ली में बाढ़ के कारण तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत के बारे में सवालों के बीच की गई।प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने तीन छात्रों की मौत का मुद्दा उठाया और बताया कि संस्थान के पास स्वीकृत भवन नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्हें उन्होंने उचित सुविधाओं के बिना माफिया बनते हुए बताया। वेणुगोपाल ने छात्रों की आत्महत्याओं पर भी चिंता जताई और मंत्रालय के पिछले जवाब का हवाला दिया। 2018-2022 के बीच, आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों में लगभग 80 छात्रों ने आत्महत्या की, जिसमें जातिगत भेदभाव एक महत्वपूर्ण कारक था। प्रधान ने जवाब देते हुए कहा कि यह सवाल दिन के एजेंडे से संबंधित नहीं था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सभी छात्रों की सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और मानसिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रतिबद्धता कोचिंग सेंटर, स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों तक फैली हुई है। प्रधान ने बताया कि कोचिंग सेंटरों पर विस्तृत दिशा-निर्देश जनवरी 2024 में सभी राज्यों को जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान, बिहार और गोवा सहित कुछ राज्यों के पास इन मुद्दों के समाधान के लिए अपने स्वयं के नियम हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पहुंचे श्रीलंका

नईदिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा क्रिकेट से छोटे से ब्रेक पर थे। उनके अलावा विराट कोहली भी ब्रेक पर चले गए थे। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों ही आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा कुलदीप यादव को भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद ब्रेक मिला था। विराट और रोहित दोनों ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। अब वनडे सीरीज के लिए पहुंच गए हैं। 30 जुलाई से भारत और श्रीलंका के बीच 2 अगस्त से वनडे सीरीज खेली जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक कप्तान रोहित, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, कुलदीप यादव और हर्षित राणा वनडे सीरीज की तैयारी के लिए कोलंबो पहुंच चुके हैं। वहीं टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर भी पालेकल से कोलंबो पहुंच गए हैं। अभिषेक नायर की देख-रेख में रोहित, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, कुलदीप और हर्षित राणा वनेड सीरीज की तैयारियों में जुटेंगे। वनडे स्क्वॉड के बाकी खिलाड़ी इस समय श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा हैं, टी20 सीरीज खत्म होने के बाद बाकी खिलाड़ी कोलंबो रवाना होंगे।

शुभमन गिल, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद फिलहाल टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं और ये सभी वनडे स्क्वॉड का भी हिस्सा हैं। टी20 सीरीज खत्म होने के बाद रवि बिश्नोई, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, सूर्यकुमार यादव और यशस्वी जायसवाल श्रीलंका दौरे से वापस लौट सकते हैं। हार्दिक पंड्या ने पहले ही साफ कर दिया था, कि निजी कारणों के चलते वो वनेड सीरीज नहीं खेल पाएंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शुरुआती बढ़त को बरकरार न रख सका सेंसेक्स

नईदिल्ली। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख की वजह से कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार 29 जुलाई 2024 को घरेलू शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 23.12 अंक या 0.03 फीसदी की बढ़त के साथ 81,355.80 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मामूली 1.25 अंक या 0.01 फीसदी की बढ़त के साथ 24,836.10 अंकों के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 416.62 अंक उछलकर 81,749.34 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, एनएसई निफ्टी 145.6 अंक की बढ़त के साथ 24,980.45 अंक के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर खुला था। बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स-निफ्टी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके।

1 अगस्त से बदल जाएंगे ये वित्तीय नियम

नईदिल्ली। अगस्त माह में धन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होंगे। हर महीने पैसों से जुड़े नियमों में बदलाव होता रहता है। इन बदलाव के पीछे कई अलग अलग कारण होते है। इस महीने यानी अगस्त में एचडीएफसी द्वारा क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों तक में बदलाव हो सकते है। बता दें कि ये बदलाव एक अगस्त से लागू होंगे। इन बदलावों से आपके खर्चे प्रभावित होंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय होती हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत का असर सभी के खर्चों पर पड़ता है। बता दें कि जुलाई में सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए थे और संभावना है कि अगस्त में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम और कम हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक ने 1 अगस्त से कई बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर उसके क्रेडिट कार्ड धारकों पर पड़ेगा।

कोलगेट-पामोलिव को 248.74 करोड़ का टैक्स नोटिस

नईदिल्ली। आय कर विभाग ने कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड को ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामले में 248.74 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। एफएमसीजी कंपनी कोलगेट-पामोलिव इंडिया लिमिटेड (सीपीआईएल) के प्रमुख ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती देंगे। यह कंपनी दांतों की देखभाल के क्षेत्र में काम करती है। वित्त वर्ष 2023-24 में सीपीआईएल की शुद्ध बिक्री 5,644 करोड़ रुपये थी। कंपनी की ओर से एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, नोटिस 26 जुलाई को मिला। ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों के लिए आयकर की मांग 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए है। सीपीआईएल ने कहा कि मांग राशि में 79.63 करोड़ रुपये की ब्याज राशि शामिल है। सीपीआईएल ने कहा कि इस आदेश के कारण कंपनी के वित्तीय संचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इंडियन बैंक का लाभ 41 प्रतिशत बढ़कर 2403 करोड़

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 41 प्रतिशत बढ़कर 2,403 करोड़ रुपये हो गया है। चेन्नई स्थित इस बैंक ने एक साल पहले इसी अवधि में 1,709 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। खराब कर्ज में कमी से बैंक के नतीजे बेहतर रहे हैं। इंडियन बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 16,945 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 14,759 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक की ब्याज आय सालाना आधार पर 13,049 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,039 करोड़ रुपये हो गई। परिसंपत्ति की गुणवत्ता के मामले में बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 30 जून, 2024 तक कुल कर्ज पर 3.77 प्रतिशत थीं।

बजट 2024 : रोजगार और छोटे कारोबार को बढ़ावा

अजीत रानाडे

पिछले मंगलवार को संसद में प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित तीसरी केंद्र सरकार का पहला बजट था। इस पूर्ण बजट ने नयी सरकार की आर्थिक नीतियों की तस्वीर पेश की है, जिसे भाजपा के एनडीए में सहयोगी दलों की सहमति की दरकार होगी। हालांकि यह बजट छह महीने के लिए लागू होगा और उसके बाद अगले वित्त वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जायेगा, इससे सरकार की आर्थिक दृष्टि की अभिव्यक्ति होती है। बजट प्रस्तावों से यह स्पष्ट है कि रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप, छोटे कारोबारों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

इसमें भारत की ऊर्जा चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है, जो कोयला एवं जीवाश्म ईंधनों से हटकर अधिक हरित एवं सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करने की प्रक्रिया में उत्पन्न हो रही हैं। इस स्थिति में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के साझा सहयोग से परमाणु ऊर्जा का उल्लेख महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, संग्रहित जल ऊर्जा की नीति भी सराहनीय है।

वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में मुख्य जोर रोजगार के अवसर पैदा करने तथा छोटे कारोबारों की मदद करने पर है। रोजगार सृजन के लिए रोजगार एवं कौशल के संबंध में प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है तथा छोटे कारोबारों के विकास के लिए आसान कर्ज मुहैया कराने और निर्यात बाजार तक पहुंच सुगम करने के प्रस्ताव हैं। पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) पर टैक्स में भी वृद्धि की गयी है। कुछ लोग इसे श्रम-आधारित वृद्धि की ओर झुकाव का संकेत मान सकते हैं, जिसमें मानव पूंजी की बेहतरी भी शामिल है। पिछले

कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ने सोच-समझकर सड़क एवं हवाई अड्डों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का हिस्सा बढ़ाया है। इन ठोस परिसंपत्तियों को तेजी से विस्तृत किया गया है और यह विकास दिख भी रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। लेकिन रोजगार के अवसर समुचित गति से नहीं बढ़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कमाई ठिठकी हुई है। रोजगार पैदा करने वाले छोटे कारोबार जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता खर्च में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से कम है। यह चिंताजनक है। केवल उत्पादन और राजस्व में प्रोत्साहन देने के बजाय सरकार ने अब अपना ध्यान रोजगार सृजन और इसके प्रोत्साहन पर केंद्रित किया है। भारत को दीर्घकालिक, सतत एवं समावेशी विकास के लिए मानव पूंजी में बड़े निवेश की आवश्यकता है। यह निवेश जीडीपी के छह प्रतिशत के स्तर पर पहुंचाना चाहिए, जो मौजूदा स्तर से दुगुना है। यह निवेश निजी और सरकारी दोनों स्रोतों से आयेगा। प्राथमिक शिक्षा और कुछ हद तक माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकारी कोष आवश्यक है क्योंकि इसके व्यापक सामाजिक लाभ हैं, जिनका दूरगामी प्रभाव होता है। लेकिन, कॉलेज और आगे की शिक्षा, जिसमें कौशल विकास और प्रशिक्षण भी शामिल हैं, पर करदाताओं का पैसा नहीं खर्च किया जा सकता है क्योंकि ऐसी पढ़ाई का लाभ मुख्य रूप से व्यक्ति को होता है और समाज पर उसका द्वितीयक प्रभाव होता है। हालांकि ऐसी शिक्षा और ऐसे कौशल विकास से उद्यमिता, अन्वेषण और रोजगार सृजन को बल मिलता है, पर इसे पूरी तरह मुफ्त मुहैया कराने का कोई ठोस औचित्य नहीं है। कौशल विकास में मुख्य चुनौती यह है कि प्रशिक्षण चाहने वाले अधिकतर युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। साथ ही, अधिकांश कौशल काम करते हुए ही सीखा जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसे राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में शामिल किया जाए, जिसमें कौशल को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। बड़ी कंपनियों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना काम करते हुए सीखने की दिशा में एक कदम है। कौशल विकास और उच्च शिक्षा का खर्च छात्रों को वहन करना चाहिए, जो उसके प्राथमिक लाभार्थी हैं। इस मामले में छात्र ऋण को सरल और सस्ता बनाकर बजट ने अच्छी मदद की है।

छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने सरकार संकल्पित: साव

छत्तीसगढ़ विजन@2047 तैयार करने संभाग स्तरीय संवाद में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है। देश के किसी और राज्य में इतने संसाधन और क्षमता नहीं है। यदि सुव्यवस्थित योजना बनाकर काम करें, तो छत्तीसगढ़ देश का सिरमौर राज्य बन सकता है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में 'छत्तीसगढ़ विजन@2047' तैयार करने राज्य नीति आयोग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय कार्यक्रम में ये बातें कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने की। कार्यशाला में बिलासपुर संभाग के युवाओं, किसानों, महिलाओं और प्रबुद्धजनों ने 'छत्तीसगढ़ विजन@2047' के बारे में अपने विचार साझा किए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संवाद कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के इतिहास में पहली बार योजना बनाने में आम लोगों से राय ली जा रही है। समाज के हर व्यक्ति को समाहित करते हुए हम योजना बनाएंगे। देश में पहली बार आपकी आकांक्षाओं और इच्छाओं का बिलासपुर और छत्तीसगढ़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास असीम संभावनाएं है। सभी को ध्यान में रखकर जब हम योजना बनाएंगे तो एक समन्वित और समावेशी विकास हो पाएगा। बिलासपुर को विश्व स्तरीय शहर बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 'अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन@2047' डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य के एक-एक व्यक्ति से सुझाव लिया जा रहा है।

बिल्हा के विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कार्यक्रम में कहा कि हमारा भारत कैसा हो, छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, इसके लिए सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार आया है। 2014 के पहले हम विश्व में 11वें पायदान पर थे। आज हम पांचवे पायदान पर हैं। सभी के सुझावों से तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट गौरवशाली होगा। बेलतरा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षो में भारत ने अभूतपूर्व तरक्की की है। छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, वन संपदा और मानव संसाधन है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 'छत्तीसगढ़ विजनञ्च2047' डॉक्युमेंट तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्राप्त सुझावों का नीति आयोग द्वारा संकलन किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन, कृषि और सर्विस सेक्टर में असीम संभावनाएं है। कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने संवाद कार्यक्रम में कहा कि संभाग स्तरीय इस कार्यशाला में आए विविध सुझावों को शामिल करते हुए प्रभावी विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। बिलासपुर संभाग के सभी जिलों से आए युवाओं, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और प्रबुद्धजनों ने परिचर्चा में शामिल होकर विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर अपने सुझाव दिए। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति ए.डी.एन. बाजपेयी, कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार और राज्य नीति आयोग के सदस्य-सचिव अनूप श्रीवास्तव भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री ने चार नवगठित नगर पालिकाओं में 'मोर संगवारी' योजना का किया विस्तार

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज लोरमी में प्रदेश की चार नवगठित नगर पालिकाओं मंदिर हसौद, बांकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में ''मोर संगवारी'' योजना का विस्तार किया। उन्होंने लोरमी के मानस मंच में आयोजित कार्यक्रम में %मोर संगवारी% एप भी लांच किया। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, दुकान एवं स्थापना पंजीयन, राशन कार्ड, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित 27 प्रकार की सुविधाएं घर पहुंचकर प्रदान की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय कार्यालयों से नागरिक सेवाएं घरों तक पहुंचाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप चरणबद्ध रूप से मोर संगवारी योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसमें 27 तरह की सेवाएं नागरिकों को बिना किसी व्यवधान और कार्यालय जाए बिना उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से कामकाज में तेजी आई है। सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हमारा संकल्प है, जिस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, उसे संवारने का काम भी हम करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगो को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए 150 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी निपटान के लिए निकायों द्वारा समग्र प्रयास किया जा रहा है।

भाजपा महिला युवा मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष ने वरिष्ठ नेत्री पर लगाए गंभीर आरोप

सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से लगाई मदद की गुहार

दंतेवाड़ा। जिला भाजपा की राजनीति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। किरंदुल की रहने वाली भाजपा महिला युवा मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष बबिता गिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वे रोते हुए कह रही हैं कि वरिष्ठ भाजपा नेत्री मीरा तिवारी, जो वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके खिलाफ बेहद गंदे आरोप लगाती हैं और किसी के भी साथ उनका नाम जोड़ती हैं।

बबिता गिरी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, यदि मीरा तिवारी जी इसी तरह करती रहीं तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। बबिता ने यह भी बताया कि जिला भाजपा के सभी पदाधिकारियों को उनकी व्यथा की जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद मीरा तिवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

बबिता ने अपने हालात का बयां करते हुए कहा, मैं किसी पुरुष भाजपाई नेता के बगल में बैठ नहीं सकती। कोई पुरुष मुझे बैठाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे भी डर है कि कहीं उसका नाम जोड़ कर उसे बदनाम न कर दिया जाए। जिला भाजपा में मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। यदि मुझे आत्महत्या करनी पड़ी तो इसके लिए सिर्फ मीरा तिवारी जिम्मेदार होंगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिला भाजपा में हड़कंप मच गया है। अब सभी की नजरें भाजपा नेतृत्व पर हैं कि वे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा नेतृत्व इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है और बबिता गिरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

जनसेवा ही हमारा परम धर्म है: लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर। ही हमारा परम् धर्म है और हम आमजन के जीवन में खुशियां लाने के प्रतिबद्ध हैं। ये वकतव्य अपने शासकीय निवास में जनदर्शन के दौरान महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कही। आज उन्होंने अपने रायपुर स्थित शासकीय आवास कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश से आए हुए

आम जनों की समस्याओं को सुना और निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। जनदर्शन में ग्राम बदनाचुआ, विकासखंड पंडरिया जिला कबीरधाम से आए हुए आदिवासी भाई बहनों की समस्या सुनी और त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे।

उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिले। सभी के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। विष्णु के सुशासन में सशक्त नारी सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देना है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि विष्णु के सुशासन में प्रदेश के किसी भी वर्ग के लोगों को समस्या ना हो इसकी जिम्मेदारी हम सभी जनप्रतिनिधियों की है। त्वरित निराकरण के निर्देश देने से खुश ग्रामीणों ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े का आभार व्यक्त किया।

साव ने विस में स्वीकारा केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास के लिये 1 रू. भी नहीं दिया

साय सरकार बताये 18 लाख में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया ?

कांग्रेस सरकार के समय भी मोदी सरकार ने राज्य के 7 लाख आवास रद्द किया था

शिवराज मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने गलत बयानी कर रहे

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास भाजपा की गरीब विरोधी चरित्र के कारण नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह गलत बयानी कर रहे कांग्रेस सरकार के समय भी मोदी सरकार ने विद्वेष पूर्वक राज्य के प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति नहीं दिया था। जब राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार थी तब मोदी सरकार ने राज्य के 7 लाख आवासों को रद्द कर दिया था। यह तर्क दिया था कि राज्यांश देरी से जमा हुआ है। जबकि राज्य सरकार ने 800 करोड़ राज्यांश जमा किया था जबकि उस समय राज्य को केंद्र से 50 हजार करोड़ विभिन्न मदों में लेना था। छत्तीसगढ़ ही नहीं तब आधा दर्जन राज्यों के मकान रद्द किया था तब भूपेश सरकार ने अपने तरफ से नये सिरे से मकानों की स्वीकृति किया था। 7 माह में साय सरकार ने एक भी नया प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किया है। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने विधानसभा में अपने जवाब में बताया कि 6 माह में केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास के लिये एक भी रूपया नहीं दिया है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवासहीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये। मोदी सरकार बताये 18 आवासों में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया? मोदी सरकार ने राज्य के 18 लाख आवासों में से 1 मकान की भी स्वीकृति नहीं दिया। साय सरकार 18 लाख आवास स्वीकृति का झूठा प्रयास कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा की साय सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के लिये नया मकान नहीं बनाया है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे है, हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद कोई नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किश्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रू. नहीं भेजा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए दावे भी जुमले साबित हुए हैं। पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 237000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार ने एक भी नया मकान स्वीकृत ही नहीं किया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

शराब घोटाला मामला: दिलीप की जमानत याचिका खारिज

रायपुर। एसीब/ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने आबकारी घोटाले मामले में डुप्लीकेट होलोग्राम

कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे ने विशेष कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. इस पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने दिलीप पांडे की याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि ईओडब्ल्यू ने प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया था. दिलीप पांडे की निशानदेही पर अनवर ढेबर के पिता की जमीन पर खुदाई के नकली होलोग्राम बाद मिले थे. वहीं ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के दौरान उपलब्ध जानकारी के आधार पर नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन आफिस के भूतल कक्ष में होलोग्राम प्रिंटिंग के सेटअप से जुड़े हुए इंडस्ट्रीयल कम्प्यूटर के हार्ड ड्राइव को, जिसके माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम के सीरियल नंबरों की छपाई की गई थी उसे जब्त किया था. इसके अतिरिक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने प्रिज्म कंपनी के नोएडा स्थित मुख्यालय से डुप्लीकेट होलोग्राम छपवा कर रायपुर तक परिवहन के लिए उपयोग में आने वाले दस्तावेज, जिसमें डुप्लीकेट होलोग्राम की संख्या एवं अन्य विवरण होते थे, आरोपी दिलीप पांडे ने उसे भी बरामद कराया था.

छत्तीसगढ़ में आज रात से बंद हो जाएंगे 150 उद्योग

रायपुर. छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई बिजली दर का विरोध उद्योगपति अब बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं. आज रात 12 बजे से करीब 150 से 200 स्टील और स्पंज के उद्योगों को बंद करने का फैसला उद्योगपति संघ ने लिया है. पहले चरण में सीएसपीडीसीएल आधारित मिनी स्टील उद्योग को बंद किया जाएगा. इसके बाद प्रदेश के 500 उद्योगों को भी बंद करने का फैसला संघ ने लिया है. अगर यह तमाम उद्योग बंद होंगे तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है. स्टील उद्योग संघ के प्रमुख अनिल नचरानी ने बताया कि बिजली दर में हालिया वृद्धि के कारण हमारी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है. यदि बिजली की कीमतों में कमी नहीं की जाती है तो यह इस्पात उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जो एक श्रृंखला प्रणाली में संचालित होता है. उच्च कीमतें इस श्रृंखला को बाधित करेंगी, जिससे महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियां उत्पन्न होंगी. उन्होंने आग्रह किया है कि इस वर्ष के लिए बिजली दर को कम करने पर विचार करें. नचरानी ने कहा, उद्योग श्रृंखला की सुचारू कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए उचित बिजली दर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है.

पीएम श्री स्कूलों में खरीदे वाद्य यंत्रों में भारी भ्रष्टाचार

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम श्री स्कूल अब घोटाला श्री स्कूल बन गया है। पीएमश्री स्कूल में वाद्य यंत्र की खरीदी के लिये 75 हजार प्रत्येक स्कूल को दिया गया था। यहां वाद्य यंत्रों के खरीदी में भारी भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का खेल खेला गया है। वाद्य यंत्र की खरीदी वास्तविक मूल्य से तीन से चार गुना ज्यादा दरों पर की गयी है। भ्रष्टाचार करने के लिए जीएसटी मुक्त वस्तुओं पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है। जब वाद्य यंत्रो की खरीदी में यह हाल है तो स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, इंडोर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स एवं गेम्स के समान खरीदी में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, इसका आकलन कर पाना संभव नहीं है। सरकार पीएमश्री में हुई आवश्यक वस्तुओं की खरीदी की जांच कराये। भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चरम सीमा पर है, हर विभाग में आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की नीति ही कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना है। 15 साल के भाजपा शासन काल में स्कूलों के बिल्डिंग के निर्माण से लेकर टेबल, कुर्सी, स्टेशनरी, साइकिल, ड्रेस एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में कमीशन खोरी का खेल होता था एक बार और वही दिन फिर आ गए हैं।

डबल इंजन की सरकार में धान को सड़ाया जा रहा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार के लापरवाही के चलते प्रदेश में 22 लाख क्विंटल से अधिक धान जिसकी कीमत 682 करोड़ रुपए से अधिक है वह खराब हो गई है। डबल इंजन की सरकार धान को सडा कर अन्नदाताओं की मेहनत का अपमान कर रही। धान का सड़ना धान घोटाला की ओर इशारा कर रहे हैं। जानबूझकर धान के रखरखाव पर लापरवाही बरता गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बीते 5 वर्षों में बंपर धान की खरीदी हुई थी और समय पर कस्टम मिलिंग हो गया था। धान के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था धान खरीदी से पहले कर दी जाती थी भाजपा की सरकार बनने के बाद धान खरीदी केंद्रो में भारी लापरवाही सामने आया है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के विकास का दावा करने वाली भाजपा की सरकार का पोल खुल गया है, उनकी ही केंद्र सरकार धान से बने चावल को संग्रहित करने में रुचि नहीं दिखा रही है जो परिस्थितियां सामने आयी है उस से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपए क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने से बचना चाहती है।

एसएसपी संतोष सिंह को मिली डॉक्टरेट की उपाधि

रायपुर. छत्तीसगढ़ कॉडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर व एसएसपी रायपुर संतोष कुमार सिंह ने एक बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है. उन्हें दुर्ग जिले के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने उनके संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों से जुड़े विषय पर किए गए शोध कार्य पूर्ण करने पर आज डॉक्टर की उपाधि प्रदान की है. उन्होंने अपना शोध कार्य निर्देशक डॉ. सुनीता मिश्रा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान शासकीय नवीन महाविद्यालय भिलाई एवं सहायक-निर्देशक डॉ. प्रमोद यादव विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, सेठ आरसीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग के निर्देशन में पूरा किया है. बता दें, स्स्क संतोष कुमार सिंह के शोध का विषय था संयुक्त राष्ट्र के शांति-निर्माण प्रयासों की भूमिका व कार्यों की समालोचना. उन्होंने पाया है कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में हिंसाग्रस्त राष्ट्रों में शांति को चिरस्थाई बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांति-रक्षा (पीस कीपिंग) और शांति-स्थापना (पीस मेकिंग) प्रयासों से आगे बढ़कर शांति-निर्माण या सुदृढ़ीकरण (पीस बिल्डिंग) कार्यों पर जोर देने की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री की पहल पर 5500 रुपये मानक बोरे की दर से दी जा रही राशि

तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ने से संग्राहकों को हुआ 18.73 करोड़ अधिक मुनाफा

रायपुर। हरा सोना के नाम से ख्यात तेंदूपत्ता का संग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त आय का स्त्रोत है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर तेंदूपत्ता का संग्रहण लघु वनोपज के रूप में किया जाता है। 12 लाख से अधिक ग्रामीण इस कार्य से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है। जिससे संग्राहकों को पहले के 4 हजार प्रति मानक बोरा की तुलना में 15 सौ रुपए अधिक मिल रहे है, इससे संग्राहकों को तेंदूपत्ता संग्रहण से होने वाली आय बढ़ी है। रायगढ़ जिले में 98 हजार 977 संग्राहकों को 68 करोड़ 68 लाख 11 हजार 180 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बढ़ी दरों के लिहाज से जिले के संग्राहकों को 18.73 करोड़ रुपए का ज्यादा मुनाफा मिला है। जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ के प्रबंध संचालक ने बताया कि रायगढ़ जिला अंतर्गत दो जिला वनोपज सहकारी यूनियन रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ में वर्ष 2024 तेन्दूपत्ता सीजन में 112 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 94 लॉट निर्धारित है। जिले में संग्रहण हेतु 747 संग्रहण केन्द्र में संग्रहण कार्य हेतु 1 लाख 40 हजार 600 मानक बोरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें तेन्दूपत्ता संग्रहण लक्ष्य के विरूद्ध 1 लाख 24 हजार 874.760 मानक बोरा संग्रहण किया गया है। इस वर्ष संग्रहण की दर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा (550 रुपये प्रति सौ गड्डी) निर्धारित है।

गेरवानी समिति फड़ सराईपाली के श्री अमृत लाल अगरिया एवं उनकी पत्नी श्रीमती पुना अगरिया ने बताया कि सीजन में उन्होंने 3640 तेन्दूपत्ता गड्डी तोड़कर उसका विक्रय किया था, जिससे उन्हें 20 हजार 20 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संवेदनशील निर्णय से हम संग्राहकों को पहले से ज्यादा राशि मिल रही है, जो हमारे लिए अतिरिक्त आय का आधार बन रहा है। इसी तरह गेरवानी समिति फड़ गौरमुड़ी के श्री नथीराम एवं उनकी पत्नी सुखमनी ने बताया कि उन्होंने 3420 तेन्दूपत्ता गड्डी तोड़कर उसका विक्रय किया था, जिससे उन्हें 18 हजार 810 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था। प्राप्त रूपये से उन्होंने बरसात में होनी वाली परेशानी को देखते हुए खप्पर वाला घर के छत की मरम्मत कराकर उसमें एस्बेस्टस की छत डलवाए हैं.

एक लाख के ईनामी समेत 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर

बीजापुर. उसूर-पामेड़ एरिया कमेटी अंतर्गत एक लाख की इनामी केएएमएस अध्यक्ष एसीएम सहित 14 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. बता दें कि इस साल अब तक 137 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. वहीं विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल 306 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है. डीएसपी सुदीप सरकार ने बताया, माओवादी संगठन में पारिवारिक सुख से वंचित रहने एवं माओवादियों की जीवन शैली व विचारधारा से क्षुब्ध होकर उसूर-पामेड़ एरिया कमेटी, गंगालूर एरिया कमेटी एवं भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 14 माओवादियों ने समर्पण किया है. ये सभी नक्सली हत्या, फायरिंग, आगजनी जैसे कई घटनाओं में शामिल थे.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.